● वर्ष-3
● अंक-154
रायपुर, मंगलवार
06 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› फायदों को जानकर आप....

पहले दिन 1 लाख 81 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन से महतारी वंदन का श्रीगणेश

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने उमड़ी भीड़

फॉर्म वितरण के पहले ही दिन रायपुर ज़िले में बंटे 20 हज़ार से ज्यादा आवेदन पत्र

रायपुर। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना का लाभ लेने पहले ही दिन 1 लाख 81 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया। योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक मद्द को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह दिखाई देने लगा है। आज रायपुर जिले में 13 हजार से अधिक आवेदन आये वहीं सुकमा जैसे प्रदेश के जनजातीय इलाकों में भी पहले ही दिन 1592 महिलाओं ने आवेदन भरा।

महिलाओं को आवेदन भरने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पुख्ता तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा कराई गई थीं। सभी जिलों में कलेक्टरों ने अधिकारियों की बैठक ली थी और निर्देशित किया था कि न्यूनतम समय में आवेदन लेने का काम पूरा किया जाए। प्रक्रिया में अधिक समय न लगे इसके लिए प्रशासन ने पात्रता संबंधी नियमों को बताने के लिए भी कर्मचारी नियुक्त किये थे। साथ ही इसके लिए आवेदन के वक्त लगने वाले जरूरी दस्तावेज बताने के लिए भी कर्मचारी तैनात किए गए है, ताकि आवेदक का आवेदन विधिवत पूरा हो जाए और स्क्रूटनी में किसी तरह की दिक्कत न आये।

प्रदेश में हर तरफ महतारी वंदन का माहौल है। धमतरी में रुद्री निवासी लोमेश्वरी ओझा जब फार्म भरने आई तो उन्होंने कहा कि मेरी छोटी-छोटी खुशियां इस राशि से पूरी होगी। मैं अपने बच्चों के लिए भी राशि खर्च कर सकूंगी। रायपुर की सविता साहू ने बताया कि तीज-त्यौहार में उन्हें, मायके से जो भेंट मिलती है, उसको वह मनचाहा खर्च करती हैं। ऐसे में मुझे मुख्यमंत्री श्री साय भी भाई की तरह लग रहे हैं, जो हर महीने तीज की राशि हजार रुपए देंगे। कसडोल विकासखंड के बल्दाकछार के विशेष पिछड़ी जनजाति की तीजबाई कमार ने कहा कि आज मैं आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची। आवेदन जमा कर दिया है। मैं मजदूरी भी करती हूँ और अब महतारी वंदन का पैसा भी मुझे मिलेगा। हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं और सरकार को धन्यवाद देती हैं।

इन जिलों से आये इतने आवेदन- आज महतारी वंदन योजना के लिए बालोद से 3226, बलौदाबाजार से 523, बलरामपुर से 783, बस्तर से 12503, बेमेतरा से 3863, बीजापुर से 710, बिलासपुर से 9329, दंतेवाड़ा से 3980, धमतरी से 3682, दुर्ग से 13997, गरियाबंद से 3723, जांजगीर से 20186, जशपुर से 5367, कांकेर से 2441, कवर्धा से 5796, कोंडागांव से 6836, कोरबा से 5101, कोरिया से 2035, महासमुंद से 7040, मुंगेली से 3263, नारायणपुर से 406, रायगढ़ से 1530, रायपुर से 13155, राजनांदगांव से 8403, सरगुजा से 1089, सुकमा से 1592, सूरजपुर से 13588, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से 4605, सक्ती से 1885, खैरगढ़-छुईखदान-गण्डई से 1552, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 955, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1654, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से 16656 आवेदन भरे गये।

रायपुर ज़िले में बंटे 20 हज़ार से ज्यादा आवेदन पत्र

राज्य में महतारी वंदन योजना के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे जिले में आज बड़ी संख्या में महिलाएं महतारी वंदन योजना के फॉर्म लेने और जमा करने के लिए लोक सेवा केंद्रों और आंगनबाडी केन्द्रों में पहुंची। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है। जिले में ऑनलाईन फॉर्म एवं ऑफलाईन पंजीयन शुरू हो गया है। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क है। आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में फार्म भरे जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। योजना हेतु फॉर्म वितरण शुरू होने के पहले ही दिन लगभग 16 हज़ार आठ सौ महिलाओं ने महतारी वंदन योजना हेतु भरे हुए आवेदन पत्र जमा किया है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया है कि जिले भर से कुल 13 हजार 155 आवेदन पहले दि नही प्राप्त हुए हैं। वहीं रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ज़ोन एक से 404 आवेदन, जोन दो से 104, ज़ोन तीन से 702, ज़ोन चार से 215, ज़ोन पाँच से 103, ज़ोन छः से 161, ज़ोन सात से 303, ज़ोन 8 से 189, ज़ोन नौ सें 337 और ज़ोन दस से 240 आवेदन पत्र शिविर एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जमा हुए हैं। इस प्रकार कुल 15 हजार 913 आवेदन पत्र पहले ही दिन प्राप्त हुए। पुरानी बस्ती निवासी श्रीमती रमा सोनकर आज लोक सेवा केन्द्र में महतारी वंदन योजना का फॉर्म लेने पहुंची। उन्होंने बताया कि आज से महतारी वंदन योजना के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसकी जानकारी मिलने पर वह लोक सेवा केन्द्र में फॉर्म लेने आई है।

छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धान खरीदी

किसानों से 144.92 लाख टन धान की हुई रिकॉर्ड खरीदी

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब तक की सबसे बड़ी धान की खरीदी हुई है। एक नवंबर से 04 फरवरी तक चले इस अभियान में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों से 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद अब तक हुई यह सबसे बड़ी धान खरीदी है। इस वर्ष 130 लाख टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया था। इस साल की धान खरीदी की तुलना करने पर यह पिछली धान खरीदी से 37.39 लाख टन अधिक है। पिछले साल 107.53 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की गई। किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान की खरीदी की गई है। वर्तमान में किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। जल्द ही अंतर की राशि का भुगतान किसानों को किया जाएगा। धान खरीदी सीजन में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों से 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है। इसके एवज में किसानों को 30 हजार 68 करोड़ 81 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों एवं किसान प्रतिनिधियों की मांग और उनकी परेशानियों को देखते हुए धान खरीदी की अवधि 31 जनवरी से बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी थी।

संसद में बोले प्रधानमंत्री मोदी

हमारे तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा भारत

नई दिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे तीसरे टर्म में देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सौफ तौर पर कहा कि जिस तेज गति से देश विकास कर रहा है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने दावा किया कि 10 वर्षों के शासन अनुभव के आधार पर, आज की मजबूत अर्थव्यवस्था और आज भारत जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। विपक्ष पर

वार करते हुए मोदी ने कहा कि हो सकता है आपके यहां मछुआरे अल्पसंख्यक न हों, हो सकता है आपके यहां पशुपालक अल्पसंख्यक न हों, हो सकता है आपके यहां किसान अल्पसंख्यक न हों, हो सकता है आपके यहां महिलाएं अल्पसंख्यक न हों। क्या हुआ है आपको? आप कब तक विभाजन के बारे में सोचते रहेंगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। शहरी गरीबों के लिए हमने 80 लाख पक्के घर बनाये। अगर ये कांग्रेस की गति से बने होते तो इस काम को करने में 100 साल लग जाते। तब तक पाँच पीढ़ियाँ बीत चुकी होंगी। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस रफ्तार के साथ काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। मोदी ने कहा कि 10 वर्ष में 40 हजार किलोमीटर रेलने ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ है। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता तो इस काम को करने में 80 साल लग जाते। उन्होंने कहा कि हमने 17 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए हैं, अगर कांग्रेस की रफ्तार से चलते तो इस काम को करने में और 60 साल लग जाते हैं। तीन पीढ़ियां धुएं में खाना बनाने-बनाते गुजर जाती।

तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी ने सेट किया टारगेट, बोले-

भाजपा को 370 तो एनडीए को 400 पार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नयी ऊर्जा देता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दिन दूर नहीं हैं। केवल 100-125 दिन बचे हैं। अबकी बार, 400 पार, इस बार हम 400 सीटों का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा को निश्चित तौर पर 370 सीटें मिलेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटे जीतेगा। उन्होंने वार करते हुए कहा कि कांग्रेस का विश्वास हमेशा एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे न कुछ सोच सकते हैं और न ही कुछ देख सकते हैं। सरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा...मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी दोहराया था कि देश को अगले हजार वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहता हूं। तीसरा कार्यकाल अगले 100 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, डिजिटल क्रिएटर्स, यूनिकॉर्न, गिग इकॉनमी - ये नए भारत की नई शब्दावली हैं। आज भारत एक अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्था है। देश में महंगाई को लेकर विपक्षी नेताओं की चिंताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इतिहास इस बात का गवाह है- जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है, महंगाई लाती है।

प्रमुख समाचार

इस्को संयंत्र के विस्तार पर 24,000 करोड़ का निवेश

कोलकाता। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अपने इस्को इस्पात संयंत्र में 40 लाख टन क्षमता की नई इकाई लगाने पर 20,000-24,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थित इस्को के मौजूदा संयंत्र में वाहन क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक फ्लैट हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) का उत्पादन करने की योजना है और इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस्को इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पीटीआई-से कहा, ''हमें नई इकाई लगाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। यह एपीआई और ऑटोमोटिव ग्रेड को लक्षित करते हुए फ्लैट एचआर कॉइल का उत्पादन करेगी।'' उन्होंने कहा, ''इस योजना को निदेशक मंडल की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है लेकिन जल्द ही यह मिलने की उम्मीद है।'' सिंह ने कहा कि वास्तविक पूंजीगत व्यय और निवेश के ब्योरे को निविदा प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। संयुक्त उद्यम के लिए संभावित विदेशी साझेदारों के संबंध में देरी होने के बाद सेल ने आखिरकार स्वतंत्र रूप से फ्लैट स्टील विस्तार परियोजना शुरू करने का फैसला किया है।

तेलंगाना में कैंपस स्थापित करने मलेशिया से मिला आवेदन

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (एफएचईआई) के परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नियामक द्वारा एक पोर्टल खोलने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को मलेशिया में एक निजी विश्वविद्यालय से तेलंगाना में एक परिसर स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। शिक्षा विभाग ने सोमवार को संसद को सूचित किया। लोकसभा के नौ सदस्यों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सरकार को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि मलेशिया के लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। 2023 को यूजीसी विनियम, 2023 को अधिसूचित करने के बाद दिसंबर 2023 में भारत में एफएचईआई परिसरों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोला। भारतीय छात्रों के लिए इन एफएचईआई की सामर्थ्य पर एक सवाल का जवाब देते हुए, सरकार ने कहा कि वे पूर्ण या आंशिक योग्यता-आधारित या आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति प्रदान कर सकते हैं और उन छात्रों को ट्यूशन शुल्क में रियायतें दे सकते हैं जो भारतीय नागरिक हैं।

केजरीवाल के खिलाफ समन रद्द करने से इंकार किया

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने संबंधी आपराधिक मानहानि मामले में आरोपी के रूप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को सोमवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल को तलब करने वाले निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि मानहानिकारक सामग्री वाले सोशल मीडिया पोस्ट को रीट्वीट करना भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि के समान होगा। अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री को रीट्वीट करते समय कुछ जिम्मेदारी की भावना अवश्य जुड़ी होनी चाहिए जिसके बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने समन रद्द करने से इनकार करने के निचली अदालत के दो आदेशों को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने मामले में पहले निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने सोशल मीडिया पेज 'आई सपोर्ट नरेन्द्र मोदी' के संस्थापक की आपराधिक शिकायत के बाद अगस्त 2019 में केजरीवाल को तलब किया था।

बहुत हो गया, कोई मस्जिद नहीं देंगे: ओवैसी

नई दिल्ली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की टिप्पणी पर बात की कि अगर ज्ञानवापी और मथुरा को शांतिपूर्वक मुक्त कर दिया गया तो हिंदू अन्य चीजें भूल जाएंगे और अन्य मुद्दे भी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की टिप्पणी को खुली धमकी बताते हुए उन्होंने कहा हम अदालतों में लड़ेंगे। अगर दूसरा पक्ष 6 दिसंबर को करना चाहता है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन हम एक बार धोखा खा चुके हैं। इतनी आसानी से दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। ओवैसी ने कहा कि हम किसी भी मस्जिद को नहीं देने जा रहे हैं, बहुत हो गया. हम कानून की अदालतों में लड़ेंगे। अगर दूसरा पक्ष 6 दिसंबर को ऐसा करना चाहता है तो हम देखेंगे कि क्या होता है। इसके अलावा, ओवैसी ने ज्ञानवापी स्थल पर लगातार नमाज अदा करने पर प्रकाश डाला, जो बाबरी मस्जिद मामले से विपरीत है, जहां तर्क मुस्लिम प्रार्थनाओं की अनुपस्थिति पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में हम नमाज अदा करते रहे हैं। बाबरी मस्जिद मामले में तर्क यह था कि आप (मुसलमान) वहां प्रार्थना नहीं कर रहे हैं।

कांग्रेस ओबीसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती: मोदी

नई दिल्ली। पूरा विपक्ष जातीय जनगणना कराए जाने के मांग कर रहा है। खुद राहुल गांधी लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जातीय जनगणना सबसे पहले कराया जाएगा। राहुल गांधी ने कई मौकों पर केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है और दावा किया है कि ओबीसी को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि देश के टॉप 100 में से सिर्फ तीन ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। सरकार ओबीसी या पिछले वर्गों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती अब इसी को लेकर राहुल गांधी पर बिना नाम लिए पीएम मोदी ने करारा वार किया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने खुद की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या आप (कांग्रेस) यहां सबसे बड़ा ओबीसी नहीं देख सकते? उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

देश को विश्वास हो चला है कि भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो, वह कानून से नहीं बच पायेगा

ललित गर्ग

झारखंड राज्य में जमीन खरीद में गड़बड़ी, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित पुराने मामलों की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से झारखंड की सरकार संकट में आ गयी और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियों ने इस समय कार्रवाई का बिगुल बजाया हुआ है, जिससे राजनीति में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का नया सूरज उदित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आदर्श एवं सशक्त होने की बड़ी अपेक्षा है। आजादी के अमृत काल में राजनीति का शुद्धिकरण एवं अपराध मुक्ति ही भारत को सशक्त एवं विकसित राष्ट्र बना सकेगा। हेमंत सोरेन के बाद अब अगला नम्बर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का है। स्पष्ट है कि अब भ्रष्टाचारियों की नैया पार होने वाली नहीं है। अगर ये लोग सोचते हैं कि ताकतवर होने के कारण कानून उन तक नहीं पहुंच सकता, तो ये मुगालते में हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी ही। भ्रष्ट आचरण से करोड़ों-अरबों की संपत्ति लूटने वाले नेतागण शायद नहीं जानते कि केंद्र में ऐसी मजबूत सरकार है, जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए तो जांच एजेंसियों को पूरी छूट मिली हुई है कि वे भ्रष्ट आचरण करने वालों को पकड़ें। दबाव मुक्त केन्द्रीय एजेंसियां अपने काम में जुटी भी हुई हैं, उनकी टांग खींचने की बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।

इन दिनों गैर-भाजपा प्रांतों में भ्रष्टाचार के मामले बड़ी संख्या में उजागर हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल आम आदमी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सतेन्द्र जैन, उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया एवं पश्चिम बंगाल में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनकी गिरफ्तारी बता रही है कि ममता बनर्जी एवं अरविन्द केजरीवाल भ्रष्टाचार मुक्त शासन के कितने ही दावे क्यों न करें, लेकिन उनके वरिष्ठ मंत्री भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं विभिन्न प्रांतों की सरकारों में भ्रष्टाचार की बढ़ती स्थितियां गंभीर चिन्ता का विषय है। ऐसा लगता है आज हम जीवन नहीं, राजनीतिक मजबूरियां जी रहे हैं। राजनीति की सार्थकता एवं साफ-सुथरा उद्देश्य नहीं रहा, स्वार्थपूर्ति का जरिया बन गया है। राजनीतिक दल अच्छे-बुरे, उपयोगी-अनुपयोगी का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मार्गदर्शक यानि नेता शब्द कितना पवित्र व अर्थपूर्ण था पर अब नेता खलनायक बन गया है। नेतृत्व व्यवसायी एवं भ्रष्टाचारी बन गया। आज नेता शब्द एक गाली है। जबकि नेता तो पिता का पर्याय था। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। पिता केवल वही नहीं होता जो जन्म का हेतु बनता है अपितु वह भी होता है, जो अनुशासन सिखाता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, विकास की राह दिखाता है। आगे बढ़ने का मार्गदर्शक बनता है।

भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण एवं जाति-सम्प्रदाय के हिंसक आग्रहों पर इंडिया गठबंधन में कोई बहस नहीं है, कोई आदर्श राष्ट्र निर्माण की दृष्टि एवं दिशा नहीं है। राजनीति में लगे लोगों में जब इन मसलों की गहराई तक जाने का धैर्य और गंभीरता चुक जाए, तो उनके मंच के संवाद पहले निम्न दर्जे तक गिरते हैं और फिर कीचड़ को ही संवाद का विकल्प मान लिया जाता है। इन दिनों यही हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए मोदी सरकार जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, वह सराहनीय है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके ऐसे नेताओं की कमी नहीं है, जो यह मानते हैं कि सरकार उनकी है और वे कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की भ्रामक सोच भारतीय राजनीति का पतन कर रही है। इसकी शुचिता और पारदर्शिता को धूमिल कर रही है। पहले राजनीति का अर्थ लोगों की सेवा करना होता था, लेकिन बाद में यह अपने लोगों की सेवा का माध्यम समझी जाने लगी। बिहार, बंगाल, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्य तो इसमें सबसे ऊपर दिखते हैं। झारखंड में ही अभी जो घटनाक्रम हुआ है, क्या उससे यह धारणा नहीं बनती कि हेमंत सोरेन ने जरूर कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि पहले उन्हें ईडी से भागना पड़ा और जब उन पर दबिश बढ़ी, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर ईडी अधिकारियों के हाथों गिरफ्तार होना पड़ा। बिहार का हाल भी झारखण्ड से अलग नहीं है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार लगातार खबरों में रहा है, वे भी सजा भुगत चुके हैं। उनके पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य परिजनों पर भी जमीन घोटाले के आरोप हैं। कहा जाता है कि जब ईडी ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछे, तो वह भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने घोटाले के वक्त खुद के नाबालिग होने की बात कही। जब ईडी अधिकारियों ने पूछा कि करोड़ों की कंपनी कैसे बनाई, तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही।

कवर्धा में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी बैठक

नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइन ऑपरेशन की तैयारी

कवर्धा। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ते नक्सली वारदातों को लेकर अब तीनों राज्यों की पुलिस सख्त रुख अपनाने जा रही है। रविवार को कवर्धा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तीनों राज्यों के उच्च अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में तीनों राज्यों के डीआईडी और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी

इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइन ऑपरेशन चलने को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिये गए है। बैठक में नक्सलियों के मुमेंट, दैनिक उपयोग के सामान अरेंजमेंट, मुखबिर तंत्र को तोड़ने और हरेक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की प्लानिंग की गई है। ताकि किसी तरह के मूवमेंट की सूचना मिलते ही एमएमसी ज़ोन द्वारा ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के खिलाफ कारवाई किया जा सके।

तीनों राज्य के आईजी और डीआईजी रहे मौजूद

इस बैठक में मध्यप्रदेश के आईजी, डीआईजी, बालाघाट एसपी, मंडला एसपी, महाराष्ट्र के आईजी, डीआईजी और तीन जिलों के एसपी और छत्तीसगढ़ आईजी, डीआईजी और कवर्धा एसपी, खैरागढ़ एसपी, राजनांदगांव एसपी समेत कई उच्च अधिकारी के साथ छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा शामिल हुए।

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस की ज्वाइन आपरेशन को एमएमसी जोन नाम दिया गया है। एमएमसी जोन के गठन के बाद कई ज्वाइंट आपरेशन भी चलाएं गए हैं। लेकिन बीतें कुछ सालों से तीनों राज्यों की पुलिस ने ज्वाइन ऑपरेशन नहीं किया है। जिसके चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में अब फिर से नक्सली वारदात बढ़ने लगी है। जिसे देखते हुए इस एमएमजी जोन को सक्रिय कर ऑपरेशन चलाने की तैयारी है।

बढ़ते नक्सली वारदात पर डीजीपी का बयान

छत्तीसगढ़ डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया कि बस्तर में नक्सली विरोधी अभियान में हमने काफी तेजी लाई है। उसी प्रकार मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों के जंगल में पुलिस को नक्सलियों की मूवमेंट की सूचना पर कारवाई में तेजी लाने के विए तीनों राज्यों की पुलिस और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर रणनीति बनाई है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाने की तैयारी है।

डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा हम नक्सलियों के मांद में जाकर कारवाई कर रहे हैं, इसलिए नक्सलियों द्वारा अटैक किया जा रहा है। इस कार्रवाई में हमें काफी कामयाबी मिल रही है। अब छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के ट्राई जंक्शन एरिया में भी इन पर कार्रवाई करने योजना बनाई गई है।

छत्तीसगढ़ डीजीपी अशोक जुनेजा ने बताया है कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई हैं। जल्द ही तीनों राज्यों की पुलिस की एक और मीटिंग करेगी। जिसमें लोकसभा चुनाव के संबंध में बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और अपराधियों के एनकाउंटर समेत कई विषयों पर चर्चा होगी।

दो ईनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार
पुलिस ने बरामद किए हथियार

कांकेर। कांकेर जिले के पुलिस ने पांच-पांच लाख के दो ईनामी नक्सली कमांडर विनोद अवलम और डिप्टी कमांडर आसू कोरसा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार बरामद किए हैं।

एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि मुजालगोंदी गांव में सर्चिंग के दौरान पुलिस ने दो नक्सली कमांडरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 बोर की बंदूक, पिस्टल समेत राउंड भी बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए नक्सली कमांडर सैनिक और आर्मी जवान की हत्या में शामिल रहे हैं।

पार्षद सलमान की बढ़ी मुश्किलें, फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला हुआ दर्ज

भिलाई। जिले के सुपेला पुलिस ने भिलाई नगर निगम के पार्षद सलमान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दरअसल, शारदापारा वार्ड 35 छावनी भिलाई के रहने वाले सलमान के ऊपर निगम चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश कर चुनाव लड़ने का आरोप है। सुपेला पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों का दुरुपयोग सहित अन्य मामले में धारा467, 468, 71 और 420 के तहत शिकायत दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और वार्ड 35 के छाया पार्षद चंदन यादव ने पार्षद सलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक साल 2021 में नगर निगम भिलाई का चुनाव आयोजित किया गया था। उसमें इंजीनियर सलमान ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज पेश करके पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षित वार्ड से चुनाव जीता है।

इस बारे में भोजराज सिन्हा ने बताया कि, भिलाई नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में पार्षद पद के चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया था। रोस्टर के मुताबिक शारदापारा वार्ड 35 को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया था। पार्षद सलमान के पास अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने किसी दूसरे की जाति प्रमाण पत्र पर अपना नाम अंकित करवाकर उसे निर्वाचन आयोग के सामने पेश किया। इसके बाद वो चुनाव लड़कर वहां का पार्षद और निगम का एमआईसी मेंबर बने। इस आधार पर सलमान का निर्वाचन फर्जी है।

वहीं, इस बारे में जब पार्षद सलमान से बात की गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।शिकायत में नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि निर्वाचन के दौरान पार्षद सलमान ने अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में जमा किया है। उसका क्रमांक 363/ब-221/2015-16 है। ये प्रमाण पत्र 15 जून 2016 में बना था। जब एसडीएम दुर्ग के कार्यालय से इस जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो इस क्रमांक का जाति प्रमाण पत्र किसी नोमिता देशमुख के नाम पर जारी होने का खुलासा हुआ। इससे साफ है कि पार्षद सलमान ने जो जाति प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन आयोग में दिया है, वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है।

मकान में प्लेट लगाने के लिए युवकों ने ऐंठे पैसे, अपर कलेक्टर के पत्र का दिया था हवाला

नंबर प्लेट के साथ लग गया चूना! जानकारी मांगी तो हो गए नौ दो ग्यारह

बालोद। डौंडी ब्लॉक में मकान नंबर का टोकन लगाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जिसमें कलेक्टर के पत्र का हवाला देकर ग्रामीणों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं।

बता दें कि रविवार को सुबह लगभग 10 बजे 2 व्यक्ति बिलासपुर पासिंग एक बाइक से डौंडी ब्लॉक के ग्राम आमाडुला पहुंचे। ग्रामीणों को बालोद जिले के अपर कलेक्टर का पत्र दिखाकर सुनियोजित तरीके से ग्रामीणों को बेवकूफ बनाने के लिए राशन कार्ड लेकर बुलाया और स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत लिखे एक टोकन पर मकान नंबर लिखकर लगाने के लिए देते हुए पचास रुपये लेना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही अज्ञात युवकों से इस संबंध में सवाल किया गया। जिसके बाद मौका पाकर दोनों युवक बाइक पर बैठकर वहां से नौ दो ग्यारह हो गए।

इससे इतर अपर कलेक्टर बालोद द्वारा जारी पत्र में उल्लेख है कि भारतीय जनकल्याण संघ, रांची (झारखंड) नाम की संस्था के सचिव मोती नायक द्वारा मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का काम करना, स्वच्छ भारत-आयुष्मान भारत तथा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा अंकित प्लेट की लागत मूल्य और लगाने के पारिश्रमिक के रूप में 50 रुपये प्रति प्लेट का भुगतान मकान मालिक से स्वेच्छा से लेने

और मकान मालिक पर दबाव नहीं डालने सहित जनपद सीईओ के द्वारा सहयोग प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है। साथ ही किसी भी जनपद/ग्राम पंचायत के कोष से कोई भी व्यय नहीं करने और किसी भी तरह के विवाद या दुरुपयोग की स्थिति में इस पत्र को शून्य माने जाने का भी उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में पड़ताल की गई तो पता चला कि कई गांवों में सरपंचों को उक्त पत्र दिखाकर और अपने झांसे में लेकर ग्रामीणों को लूटने के लिए गांव में मुनादी तक करवा दी गई है। डौंडी सीईओ डीडी मंडले से इस संबंध में जानकारी ली गई तो 2 फरवरी को ब्लॉक के समस्त सरपंचों और सचिवों के नाम से मकान नंबर प्लेट लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का पत्र जारी करने की बात कही गई।

जंगल बचाने के लिए अस्तु नाग का अनोखा कदम

साइकिल से देश भ्रमण पर निकला नौजवान

कांकेर। जल, जंगल और जमीन ये वो चीजें हैं जिनके लिए जीवन भर आदिवासी समाज संघर्ष करता है। लेकिन विकास की वेदी के लिए सबसे पहले इन्हीं तीनों चीजों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। वैसे तो इन तीन चीजों के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती।फिर आज का मानव अपनी तरक्की के लिए इन्हीं सबसे जरुरी चीजों की बलि दे देता है। ये जानते हुए कि जमीन और जंगल सीमित है फिर भी इनका दोहन होता है।लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीजों का मूल्य समझते हैं।साथ ही साथ दुनिया को भी प्रकृति का मोल समझाने के लिए अभियान में जुट गए हैं।

जंगल को बचाने और पर्यवारण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 साल का नौजवान अभियान पर निकला है।इस युवक का नाम है अस्तु नाग।जो जगदलपुर के पुसपाल ब्लॉक में रहता है।ये युवक अगले डेढ़ साल तक देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों से जंगलों को बचाने की अपील करेगा।अपनी यात्रा की शुरुआत अस्तु नाग ने दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद लेने के बाद की।

अस्तु ने बताया कि मेरा उनका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से पेड़ कट रहे हैं, उनका रोका जाए। क्योंकि जंगल हमारे लिए काफी जरुरी हैं।अस्तु भारत भ्रमण करके लोगों को पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का संदेश देना चाहते हैं। अस्तु आगे कहते है सब अपने में मगन हैं कोई ध्यान नहीं देता है। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि पेड़ों को बचाने के लिए ज्यादा कुछ कर सकूं।इसलिए सोचा कि जब सब पढ़े लिखे भाई अपने में मगन हैं तो मैं यही काम कर लेता हूं।

अस्तु नाग ने कहा हसदेव अरण्य में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए हैं। जिसकी जानकारी समाचार पत्र और टीवी चैनल के माध्यम से मिली। तब से मैं बहुत दुखी हूं। हमारी जिंदगी का सहारा ये पेड़ ही हैं। लेकिन कुछ लोग इन पेड़ों को काट रहे हैं यह ठीक नहीं है। आने वाले समय में जंगल खत्म नहीं हो इसी उद्देश्य को लेकर यात्रा कर रहा हूं,जो डेढ़ साल तक चलेगी। अस्तु नाग की उम्र भले ही कम हो लेकिन उनकी सोच दूसरों को जागरुक करने की है। अस्तु का मानना है कि उनके इस अभियान से जनजागरुकता फैलेगी और लोग पेड़ों के महत्व को समझेंगे।इसी लक्ष्य को लेकर अस्तु नाग पहले भी पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण कर चुके हैं।

पालिका अध्यक्ष ने बचाई अपनी कुर्सी, ध्वस्त हुआ अविश्वास प्रस्ताव

कांग्रेसियों ने मनाई खुशी

अभनपुर। नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध भाजपा और निर्दलीय पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज ध्वस्त हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई ने आज सुबह 11 बजे पालिका के सभागार में कार्यवाही शुरू की। मतदान के बाद अध्यक्ष मध्यानी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 मत और विपक्ष में 11 मत पड़े। वहीं 2 मत निरस्त घोषित हुए।

वहीं उपाध्यक्ष जगत के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में भी 8 मत और विपक्ष में 12 पड़े। 1 मत निरस्त घोषित हुआ, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए 14 मत चाहिए थे। इस प्रकार अध्यक्ष मध्यानी और उपाध्यक्ष जगत की कुर्सी बच गई।

अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त होने पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर पूर्व क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू भी पालिका पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर और पालिका कार्यालय के बाहर जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशी मनाई। बता दें कि 21 सदस्यीय पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हैं। वहीं भाजपा के 8 और 2 निर्दलीय पार्षद हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अतिक्रमण पर चला बुलडोजर 47 दुकानों को प्रशासन ने तोड़ा

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा के गृह नगर कवर्धा में सोमवार को अवैध कब्जा पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। शहर के कलेक्टोरेट रोड स्थित भोजली तालाब के पास अंजुमन जमात खाना की बाउंड्रीवॉल समेत अन्य लोगों के 47 दुकानों में प्रशासन का बुलडोजर चला है। यह कार्रवाई नगर पालिका और राजस्व विभाग के टीम ने की है। जानकारी के अनुसार, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई की शुरूआत सोमवार सुबह नौ बजे से शुरू हुई। जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध अतिक्रमण किए हुए लोगों को दो फरवरी को नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके कारण कार्रवाई की गई। दूसरी ओर अतिक्रमण की कार्रवाई से दुकानदार नाराज हैं। दुकानदारों का कहना है कि वे इस जगह में बीते 10 वर्ष से छोटी-मोटी दुकान लगाकर काम कर रहे हैं। बीते 10 वर्ष में उन्हें नहीं हटाया गया। अब कार्रवाई की जा रही है। इससे अब वे बेरोजगार हो जाएंगे। दुकानदारों ने जिला प्रशासन से किसी भी अन्य स्थान पर में जगह देने की मांग की है।

अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार माजदा वाहन, नौ घायल

जांजगीर चांपा। अकलतरा थाना क्षेत्र के पिपरसत्ती गांव में मोड़ के पास तेज रफ्तार माजदा वाहन अनियंत्रित होकर पलटी गई। माजदा वाहन में 30 लोग सवार होकर चमत्कारी तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे। इसमें से एक बच्ची सहित नौ लोगों को चोट आई है। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी अनुसार, अकलतरा थाना क्षेत्र के मधुवा गांव के रहने वाले सभी 30 लोग सोमवार सुबह करीब पांच बजे अपने घर से माजदा वाहन में सवार होकर मुंगेली जिले के पेंड्री गांव के तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे। माजदा वाहन चालक तेज रफ्तार से चला रहा था। पिपरसत्ती गांव पहुंचे थे, तभी वाहन चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे की तालाब में माजदा वाहन जा पलटी। हादसे से लोगों में चीख-पुकार मच गई और ग्रामीणों की मदद से माजदा वाहन में फंसे लोगो को बाहर निकाला गया। हादसे में उमेद बाई, सविता बाई, राधा बाई, तेरस बाई, बेन बाई, निशा कुमारी, फूलचंद, महावीर कैवर्त और नरेश कुमार घायल हुए हैं।

डीआईजी दीपक झा बनाए गए राजनांदगांव के नए आईजी

राजनांदगांव। पुलिस महकमे में एक महत्वपूर्ण फेरबदल रविवार की देर रात हुआ जिसमें डीआईजी दीपक झा को राजनांदगांव का नया आईजी बनाया गया है। 2007 बैच के आईपीएस झा ने अपनी सर्विस की शुरूआत एसडीओपी के तौर पर अविभाजित राजनांदगांव के खैरागढ़ से की थी। उस दौरान उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया था। जिसके चलते खैरागढ़ में खलबली मच गई थी। वहीं उन्होंने नक्सल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। सरकार ने झा को हाल ही में मुख्यमंत्री के सचिव बने राहुल भगत की जगह आईजी पदस्थ किया है। हालांकि झा प्रभारी आईजी की हैसियत से रेंज के चार जिलों को सम्हालेंगे। पुलिस महकमे में झा की अच्छी साख है। उन्हें नियम पसंद अफसर माना जाता है। झा ने एसपी के रूप में कोंडागांव, महासमुंद, बालोद, बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर और बलौदाबाजार जिले में कार्य किया। वर्तमान में झा डीआईजी पद पर पदोन्नत हैं। प्रभारी आईजी के रूप में उन्हें राजनांदगांव भेजा गया है।

बेटी की शादी में आए मेहमानों को पिता ने बांटे हेलमेट

कोरबा। शादी का सिलसिला शुरू हो गया है। शादी के इस सीजन में लोग कुछ खास और अलग करना चाहते हैं। कोरबा में बस इसी तरह एक अलग ही अंदाज में शादी का नजारा देखने को मिला। यहां शादी में बाइक से आए लोगों को हेलमेट बांटा गया। इतना ही नहीं, लोगों ने हेलमेट पहनकर डांस भी किया और लोगों को सुरक्षा को लेकर जागरुक किया है। जानकारी के अनुसार, मुड़ापार के रहने वाले सेद यादव के परिवार में 38 सदस्य हैं। सेद कुमार यादव की बड़ी बेटी नीलिमा यादव स्पोर्ट्स टीचर हैं। नीलिमा की शादी बिलाईगढ़ जिले के लंकाहुडा गांव में रहने वाले खम्हन यादव से हुई। शादी कार्यक्रम के दौरान उनके यहां बाइक से आए मेहमानों को हेलमेट देकर सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जागरूक किया। घर के सदस्यों ने हेलमेट पहनकर डांस किया और लोगों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम काफी मनमोहक था, जिसे देखने आसपास की बस्ती के लोग भी पहुंचे हुए थे। हेलमेट डांस में 12 सदस्यों ने डांस किया।

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए शिविर

महासमुंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने सभी अनुभागीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों को हल्का पटवारी स्तर पर ग्राम वार शिविर लगाकर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए है। जिसके तहत महासमुंद अनुविभागीय अधिकारी श्री उमेश साहू ने महासमुंद अंतर्गत बी-1 पठन पाठन/ अन्य कार्य हेतु शिविर आयोजन करने ग्राम तिथि वार सूची जारी की है। उन्होंने समस्त हल्का पटवारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ ग्रामों के कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराकर निर्धारित तिथि में आयोजित शिविर में बी-1 पठन पाठन एवं अपने दायित्व से संबंधित कार्य कराएं। साथ ही अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के मामलो की ऑनलाईन भूईया में दर्ज करना, नवीन ऋणपुस्तिका बना कर प्रदाय करना, भू-अभिलेखो की नकल प्रदाय करना, नक्शा बटांकन एवं सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त कर निराकरण करना,जाति प्रमाण हेतु वशांवली तैयार कर प्रदाय करना एवम राजस्व से संबंधित अन्य कार्य संपादित करना सुनिश्चित करे।

घर में घुसकर कानून के रखवालों ने वकील दंपति को पीटा

- **बेलगाम पुलिस की गुंडागर्दी! हिरासत में रखकर नहीं करा रहे मुलाहिजा,एसएसपी साहब आखिर कब होगी कार्रवाई?**

बिलासपुर। सरकंडा थाना के डायल 112 की टीम पर वकील दंपति ने जबरन मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर अधिवक्ता संघ ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। पीड़ित अधिवक्ता अनुराग पांडेय ने डायल 112 में तैनात आरक्षक और ड्राइवर पर घर से निकालकर की मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद नाराज वकीलों में आक्रोश है और वे 112 के ड्राइवर और आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें तत्काल सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं।

सरकंडा क्षेत्र के जोरापारा निवासी अनुराग पांडे जिला कोर्ट में अधिवक्ता है। उनकी पत्नी शासकीय शिक्षक हैं। रविवार को दोनों अपने घर पर थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस बीच पत्नी के भाई ने डायल 112 को फोन करके बुला लिया। पत्नी ने आरोप लगाया है कि डायल 112 के स्टाफ ने जबरन घर के अंदर घुसकर अनुराग से मारपीट की है। बीच-बचाव करने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी गाली-गलौज की। इसके बाद पुलिसकर्मी अनुराग को थाना ले गए। मारपीट से अनुराग को चोट लगी है। सरकंडा पुलिस ने अनुराग का मुलाहिजा नहीं कराया। उल्टा हिरासत में रखा है। इसके अलावा मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पीड़ित अनुराग की पत्नी ने डायल 112 के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाना में लिखित में शिकायत की है। वकील के घर और आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा है। वकील के साथ मारपीट करते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। इसके बावजूद सरकंडा पुलिस द्वारा डायल 112 के स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

घटना के दूसरे दिन वकीलों का पूरा समूह एसपी और आईजी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने इस घटना को लेकर दो दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है।

घर-घर सर्वे करके महतारी वंदन योजना का भरवाया जा रहा फॉर्म

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को 10 हजार फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगी। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र हैं। योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी से ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी हैं। अनंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अनंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ बजट सत्र : राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

बोले- वादे पूरे करने की दिशा में उठाए ठोस कदम, छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना होगी शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ की 6वीं विधानसभा के दूसरे सत्र को संबोधित किया। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल हरिचंदन का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ सरकार की अब तक की उपलब्धियों को राज्यपाल ने सदन में गिनवाया।

राज्यपाल के अभिभाषण से जुड़े प्रमुख बिंदू

1. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने सबसे पहले कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्ष 2024 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

2. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ की छठवीं विधानसभा का गठन दिसम्बर 2023 में हुआ था। 20 दिसम्बर 2023 को नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के अपने अभिभाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी तथा वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे खुशी है कि अल्प अवधि में मेरी सरकार ने जनता से किए गए वादे पूर्ण करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है।

3. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार ने 'समृद्ध किसान-संपन्न प्रदेश' की अवधारणा पर तेजी से अमल साल के धान के बकाया बोनस 3 हजार 716 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है।

4. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा भी निभाया गया और धान खरीदी की पारदर्शी और सुगम व्यवस्था भी की गई, जिससे इस वर्ष छत्तीसगढ़ में अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

5. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि 'जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान' ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, आवश्यक अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी विषयों पर तेजी से काम किया जाएगा।

6. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के द्वारा पीवीटीजी अर्थात् विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे-पक्के आवास गृह, संपर्क सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टॉवर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल से परिपूर्ण करने हेतु मेरी सरकार कृत संकल्पित है। पीएम जनमन महाअभियान के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, उपचार एवं दवा वितरण हेतु 66 चलित चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

7. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि तेन्दूपत्ता, महुआ, इमली सहित सभी लघु वन उपजों से

जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रूपये प्रति मानक बोरा तथा संग्राहकों को 4500 रूपये तक बोनस प्रदाय किए जाने हेतु मेरी सरकार कटिबद्ध है। संग्राहकों और उनके परिवारजनों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा व चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्थानीय रहवासियों को सक्षम बनाया जाएगा।

8. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना'' के लाभ से वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं मेरी सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए श्जल जीवन मिशनश् के कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु अग्रसर हुई है। यह मेरी सरकार की न्यायप्रियता और संवेदनशील नजरिए की एक बड़ी मिसाल है।

9. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि सुदृढ़ पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांवों में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना के साथ ही आजीविका के नए साधन पहुंचाने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। इससे प्रदेश के गांव आर्थिक स्वावलंबन, पारंपरिक सम्मान और सामाजिक चेतना के नए शक्ति केन्द्र बनेंगे।

10. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ''वन नेशन वन राशन कार्ड'' योजना, ''ई-पॉस मशीन'' के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरी सरकार ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के अंतर्गत दिसम्बर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67 लाख 94 हजार अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा।

11. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि महिलाओं का जीवन आसान बनाने में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की बड़ी भूमिका रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।

12. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार ने पुलिस बल को अपने कर्त्तव्य निर्वहन हेतु सशक्त बनाने के लिए एक ओर उन्हें नई सुविधाओं से सज्जित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर उनकी समस्याओं के समाधान हेतु मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार व अन्य आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर गुणवत्ता के उपकरण दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास हेतु लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएंगे। मेरी सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है तथा छत्तीसगढ़ को पूर्णतः नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने हेतु कटिबद्ध है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है।

13. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार ने पुलिस कर्मचारियों की कठिन सेवा, लगन, कर्त्तव्यनिष्ठा का सम्मान करते हुए मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक को एक दिवस का साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा। अवकाश की पात्रता, प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

14. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, वनवासी एवं अन्य अंचलों की संस्कृतियां, विभिन्न अंचलों के पर्व-त्यौहार, जन आस्था केन्द्रों जैसे अवयवों को समग्रता से देखते हुए सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का ताना-बाना बुन रही है। 5 शक्ति पीठों-कुदरगढ़, चन्द्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसी तरह स्थानीय विशेषताओं को पर्यटन विकास का केन्द्र बनाया जाएगा।

15. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि राजिम कुंभ (कल्प) 3 जीवनदायिनी नदियों का त्रिवेणी संगम ही नहीं है बल्कि इसके माध्यम से आस्था, समरसता और स्थानीय विकास की त्रिवेणी भी विकसित हुई थी। देश और दुनिया के तीर्थ मानचित्र में राजिम कुंभ (कल्प) को अत्यंत सम्मानजनक स्थान दिलाने में मेरी सरकार निरंतर प्रयासरत् है।

16. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि अयोध्या धाम में प्रभु रामलला की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा से पूरी दुनिया में अभूतपूर्व उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ है, जिसे और अधिक बढ़ाने हेतु मेरी सरकार द्वारा 5000 पंजीकृत रामायण मंडली, भजन मंडली को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। मेरी सरकार छत्तीसगढ़वासियों के लिए रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का वादा निभाने जा रही है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष हजारों तीर्थयात्री अयोध्या धाम सहित काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

17. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44 प्रतिशत वन क्षेत्र होना प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। वन संसाधन प्रदेश के पर्यावरण संतुलन और अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार कैम्पा मद सहित विभिन्न वित्तीय संसाधनों का उपयोग वनों के साथ वन संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन में करेगी। वनवासियों तथा वन आश्रितों के लिए पर्यावरण सम्मत आजीविका के साधन विकसित किए जाएंगे। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वन के प्रबंधन में वनवासियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही हमने 'प्रोजेक्ट बघवा' 6 की शुरूआत कर बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

18. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास की रणनीति बनाई है, जिसके तहत स्कूल से कॉलेज तक गुणवत्तापूर्ण-संस्कारयुक्त-रोजगारपरक शिक्षा अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। विद्यार्थियों को नवाचार और रचनात्मक कार्यों में दक्ष बनाने के लिए साइंस सेंटर रायपुर में ''इनोवेशन हब'' की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में वहां की विशेषताओं के अनुरूप खेल अकादमी, खेलो इंडिया लघु केन्द्र, खेल स्टेडियम आदि सुविधाओं का समुचित विकास किया जाएगा। किए गए वादे अनुरूप संपूर्ण प्रदेश में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने हेतु मेरी सरकार ठोस कदम उठा रही है।

19. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मेरी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा की छूट अवधि पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। मेरा विश्वास है कि इन कदमों से विद्यार्थियों और युवाओं का विश्वास लौटेगा और वे नए सिरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होंगे।

20. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार महिलाओं और शिशुओं की समुचित देख-रेख, सुरक्षा और स्वस्थ विकास के प्रति सजग है। कुपोषण की रोकथाम के लिए ''मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना'', ''वजन त्यौहार'', ''पूरक पोषण आहार योजना'', ''रेडी-टू-ईट पोषण आहार'' जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सफलता के अनेक सोपान तय किए गए थे। इन्हें अब आगे बढ़ाने तथा इनमें नए आयाम जोड़ने के लिए मेरी सरकार तत्पर है। 'सखी-वन-स्टाप सेंटर', 'महिला हेल्प लाइन', 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना', 'छत्तीसगढ़ महिला कोष', 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' जैसी सुविधाओं का विस्तार बेहतर रूप में किया जाएगा। मेरी सरकार मातृ शक्ति को सम्मान और अधिकार प्रदान करने के लिए समुचित योजनाएं संचालित करेगी।

21. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि विवाहित महिलाओं को अपनी सामाजिक स्थिति अनुसार जिम्मेदारियों के निर्वाह में मदद के लिए मेरी सरकार ने ''महतारी वंदन योजना'' प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 12000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की गई है।

22. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार प्रदेश में अच्छी सड़कों, सिंचाई से लेकर पेयजल तक पर्याप्त पानी, निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा टेक्नॉलॉजी से बेहतर तथा पारदर्शी जन-सेवाएं, आईटी तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जैसी व्यापक अधोसंरचना का विकास करेगी।

23. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न संसाधनों के युक्तियुक्त उपयोग से उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी लाई जाएगी। मेरी सरकार एक ओर जहां प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि के लिए संकल्पित है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य के विकास का लक्ष्य प्रदेश के जन-जन का सशक्तीकरण होगा।

24. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि प्रदेश को सिकलसेल एनीमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त सिकलसेल मरीजों को निःशुल्क दवाइयां तथा परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

25. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार प्रदेश में निवेश का आदर्श वातावरण बनाएगी, जिसमें निवेशकों के साथ ही जनता के हित भी कानूनी रूप से सुरक्षित रहें। मुआवजा, पुनर्वास पैकेज जैसे हर प्रावधान में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

26. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि मेरी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए संकल्पित है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यों का सतत् मूल्यांकन करेगी। इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर समीक्षा हेतु ''इंडिकेटर फ्रेमवर्क'' की मदद ली जाएगी। विकास संबंधीगुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आंकड़ों के लिए ''अटल पोर्टल'' जैसे अत्याधुनिक साधन का उपयोग किया जाएगा।

27. राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि यह युग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में तेज प्रगति का है। देश और दुनिया से मुकाबला करने और अपनी जगह बनाने के लिए नागरिकों के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी नवीनतम जानकारी और टेक्नॉलॉजी से सशक्त होना आवश्यक है। मेरी कामना है कि आप सभी सदस्यगण नई सोच और नए साधनों के उपयोग से जनहित और विकास के नए शिखर को स्पर्श करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे अर्जित करने के लिए अपनी पूरी प्रतिभा, लगन और मेहनत से जुट जाएंगे। मेरी कामना है कि आपके योगदान से छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी दिशाओं में फैले।

अनुपूरक बजट में 12 हजार करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान

सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी। जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है। बता दें कि भाजपा ने चुनाव में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का वादा किया था। अभी फिलहाल समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। कृषक उन्नति योजना से किसानों को अंतर की राशि दी जाएगी। कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ के किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू करने की घोषणा की गई थी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसान से धान की खरीद की जाएगी। किसान से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर किसान से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा बोरियो की उपलब्धता भी धान खरीदने से पहले सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को एक किश्त में पूरा भुगतान मिल जाए और उनको लम्बी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर पंचायत भवन में बैंको में नगद आहरण काउंटर स्थापित किए जाएगे।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में रेंज आईजी समेत 25 जिलों के एसपी का तबादला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजपी की सरकार बनने के बाद पहली बार बड़ी संख्या में आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला किया गया है। जिस ट्रासफर लिस्ट का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आधी रात जारी कर दी गई है। राज्य शासन ने रेंज आईजी और 25 जिलों के पुलिस कप्तानों का ट्रांसफर कर उन्हें नई जगह पर पदस्थ किया है। गृह विभाग ने कुल 44 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला किया है। केंद्र से डेपुटेशन पर लौटे अमरेश मिश्रा को रायपुर संभाग का नया आईजी बनाया गया है। साल 2011 बैच के आईपीएस संतोष कुमार सिंह को रायपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। वहीं रायपुर के वर्तमान एसएसपी प्रशांत कुमार अग्रवाल को बस्तर संभाग भेज दिया गया है। इसके साथ ही आईपीएस डॉ. आनंद छाबड़ा, अजय कुमार यादव, बद्री नारायण मीणा को पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। आईपीएस दीपांशु काबरा को परिवहन विभाग से हटाकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा जशपुर के एसपी आईपीएस डी. रविशंकर को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। इस सम्बंध में अवर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं।

किसान दर-दर भटक रहे हैं, धान का नहीं दे रहे 3100 : पूर्व सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। भूपेश बघेल ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा सरकार होर्डिंग में है। धान का 3100 नहीं दे रहे, किसान दर-दर भटक रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त सरकार ने नहीं दी है। हम किसानों के लिए आम जनता के लिए एटीएम थे। यह तो बैंक बन गए हैं, सीधा पैसा अडानी को जाता है। भूपेश बघेल ने आगे कहा, ना किसानों को पैसा दिया, ना तो महतारी वंदन के तहत पैसा मिला। पिछले सत्र में महतारी वंदन योजना की बात बढ़ चढ़कर की गई।

बजट को लेकर वित्तमंत्री ओपी चौधरी पर भूपेश बघेल का पलटवार

रायपुर। नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व सीएम बघेल उनके कई सवालों का जवाब दिया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 11 लोकसभा के सभी जो दावेदार थे, उनके नाम पर चर्चा हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की यह दूसरी बैठक थी। अब इस कमेटी का काम खत्म हो गया है। अंतिम फैसला अब कांग्रेस सीईसी की बैठक में लिया जाएगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को दिवालियापन की तरफ धकेल दिया था, उस मोड पर हमारी सरकार बजट ला रही है। ओपी चौधरी के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा हमने कभी रोना नहीं रोया। केंद्र सरकार कितना अड़ंगा लगाए, उसके बावजूद भी, चाहे किसानों के, मजदूरों के जितने वादे हमने किए थे, उसको एक-एक करके हमने पूरे किए। अब वादे नहीं पूरा करना है, इसलिए वह बहाना ढूंढ रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, पीएम मोदी

कहते हैं कि आजादी के बाद जो लोग वर्षों तक सत्ता में रहे, वे भी पवित्र पूजा स्थलों के महत्व को नहीं समझ सके। पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार के समय सोमनाथ मंदिर के निर्माण को याद दिलाया है।

भूपेश बघेल ने कहा सोमनाथ मंदिर किसने बनाया था गुजरात का, इन्होंने बनाया था ? और धर्मस्व विभाग रहा है, धार्मिक न्यास भी रहा है, सारी व्यवस्थाएं थी। यह तो उसी प्रकार की बात हुई, जैसे लोग कहते हैं 2014 के बाद देश को आजादी मिली। यह उसी प्रकार की बातें हैं।

इंडिया गठबंधन पर बसपा सांसद मलूक नागर का बयान सामने आया था। जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता चुनाव के दौरान मंदिरों में जाते हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ बोलते हैं। जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मंदिर जाना एक व्यक्तिगत आस्था की बात है। सनातन की बात है तो सनातन किसे कहते हैं। मैं पहले भी कई बार इसे बोल चुका हूं, सनातन की परिभाषा बताएं और क्या वह सनातन के हिसाब से चल रहे हैं।

भूपेश बघेल ने कहा सवाल यही उठता है जो जगतगुरु शंकराचार्य ने सवाल उठाए, करपात्री जी महाराज ने सबसे पहले उठाया था। वर्तमान में जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कहा कि आरएसएस का कोई ग्रंथ नहीं है। उनका ना कोई गुरु है। यह पहले बताएं इनके धर्म ग्रंथ क्या है और उनके गुरु कौन है। ये शंकराचार्य के सवाल हैं, यह मेरे सवाल नहीं है। इनको बताना चाहिए।

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी के छापा को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं को दबाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है, कांग्रेस के नेताओं को दबाने और बदनाम करने के लिए विधानसभा चुनाव के पहले जो हो रहा था। अब यह लोकसभा चुनाव के पहले फिर से किया जा रहा है। यह हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है।

लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव नजदीक है तो राजनीतिक बयानबाजी भी शुरु हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल एक दूसरे पर शब्दों के बाण चला रहे हैं। यह कुछ दिनों बाद और तेज हो जाएगा। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी के आरोपों और बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।

जन चौपाल में लैपटॉप की मांग लेकर पहुंचे दृष्टिबाधित प्रकाश

■ **कलेक्टर डॉ सिंह ने दिया जल्द लैपटॉप दिलाने का आश्वासन**

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह की जनचौपाल में अब सिर्फ मांग और शिकायतों के आवेदन ही नहीं, बल्कि धन्यवाद सन्देश भी आने लगे हैं। आज सोमवार को आयोजित जन चौपाल में प्रोफेसर कॉलोनी निवासी श्री प्रदीप मिश्रा एवं कुशालपुर निवासी श्री जीतू ने अपनी शिकायतों का त्वरित निराकरण होने पर कलेक्टर डॉ सिंह को पुष्प गुच्छ देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही छात्र श्री प्रकाश साहू ने पढाई के लिए अच्छे रैम के लैपटॉप के लिए आवेदन दिया। कचना निवासी श्री प्रकाश साहू दृष्टिबाधित हैं और बी.ए. पाठ्यक्रम के छात्र हैं। उन्होंने जनचौपाल में कलेक्टर को बताया कि उनके कोर्स के लिए ज्यादा स्टोरेज और तेज प्रोसेसिंग वाले उपकरण की आवश्यकता है और

मोबाइल पर पढाई करने में उन्हें असुविधा होती है। उन्होंने कलेक्टर से ज्यादा रैम वाले लैपटॉप की मांग की जिससे वो पढाई में बेहतर प्रदर्शन कर अपना भविष्य बना सकें। कलेक्टर ने सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांग को सुना और सम्बंधित विभाग के अधिकारी को यथासंभव निराकरण करने के निर्देश दिए। विगत जनचौपाल में श्री प्रदीप मिश्रा अपने निवास के सामने की सड़क पर स्थित चैम्बर में ढक्कन नहीं होने की समस्या लेकर आये थे। ढक्कन नहीं होने के कारण सड़क पर चलते हुए एवं वाहन चलाते हुए दुर्घटना होने का खतरा जनचौपाल में आवेदन देने के 4 दिन के भीतर ही चैम्बर में ढक्कन लग गया। इसी प्रकार कुशालपुर निवासी जीतू ने अपने क्षेत्र में अवैध वसूली की शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर डॉ सिंह ने त्वरित कार्यवाही की। श्री जीतू ने आज कलेक्टर को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि उन्हें और बाकी व्यापारियों को अवैध वसूली बंद होने से काफी राहत मिली है। जनचौपाल में आज कुल 92 आवेदन प्राप्त हुए। राजा तालाब की निवासी श्रीमती ज्योति यादव ने नया राशन कार्ड बनवाने, सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुरेश दीवान ने स्कूल के बिजली बिल का नियमित भुगतान सुनिश्चित करवाने, ग्राम डोमा निवासी श्री कुमार यादव ने आबादी भूमि में अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में, ग्राम सण्डी के श्री डेमेश्वर कुमार ने बी.एड की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त सहायता राशि का चेक रूका होने, लक्ष्मण नगर निवासी श्री राजेश यादव ने नामांतरण के लिए पैसे की मांग किए जाने और परशुराम नगर निवासी श्री अमित पवार ने मकान की छत के उपर से हाई टेंशन विद्युत पोल हटवाने हेतु आवेदन दिए। कलेक्टर डॉ सिंह ने सभी आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को मार्क करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

कई जिलों के एसपी बदले, संतोष सिंह रायपुर के एसपी बने, काबरा की जगह डी. रविशंकर को परिवहन

रायपुर। राज्य सरकार ने रविवार देर रात आइपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों का नाम भी शामिल है। जारी आदेश के मुताबिक 2011 बैच के आईपीएस संतोष सिंह अब रायपुर के नए एसपी होंगे। इससे पहले रायपुर की कमान संभाल रहे प्रशांत अग्रवाल को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बस्तर क्षेत्र में उप पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रतन लाल डांगी को रायपुर आइजी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। डेपुटेशन पर केंद्र से लौटे अमरेश मिश्रा अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। 2004 बैच के संजीव शुक्ला अब बिलासपुर आईजी होंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक डा. आनंद छाबड़ा, अजय कुमार यादव, बद्री नारायण मीणा को पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है। दीपांशु काबरा की सेवाएं परिवहन विभाग से वापस लेते हुए उन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक जशपुर डी. रविशंकर को अब अतिरिक्त परिवहन आयुक्त बनाया गया है।

जारी आदेश के अनुसार एमआर अहिरे को सूरजपुर, दीपक झा को राजनांदगांव, इंदिरा कल्याण एलेसेला को कांकेर, आशुतोष सिंह को महासमुंद, विवेक शुक्ला को जांजगीर चांपा, शशि मोहन सिंह को जशपुर, विजय अग्रवाल को सरगुजा, रामकृष्ण साहू को बेमेतरा, जितेंद्र शुक्ला को दुर्ग, दिव्यांग पटेल को रायगढ़ जिले का एसपी बनाया गया है। वहीं शलभ सिन्हा को जगदलपुर, भावना गुप्ता को गौरेला पेंड्रा मरवाही, सूरज सिंह को कोरिया, सिद्धार्थ तिवारी को कोरबा, जितेंद्र यादव को बीजापुर, आंजनेय वार्ष्णेय को धमतरी, अंकिता शर्मा को सक्ती, रजनेश सिंह को बिलासपुर व सरजु राम भगत को बालोद जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

राहुल सरकार को अर्थव्यवस्था पर ज्ञान ना ही दें तो अच्छा है

नीरज कुमार दुबे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जैसे ही निकले वैसे ही उनकी पार्टी और इंडी गठबंधन से नेताओं और दलों का निकलना शुरू हो गया। राहुल गांधी के यात्रा पर निकलने से पहले ही मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ गये। राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर बिहार पहुँचते उससे पहले ही नीतीश कुमार गठबंधन का साथ छोड़ गये। राहुल गांधी बंगाल पहुँचे तो ममता बनर्जी ने भी गठबंधन से अलग होने का संकेत देते हुए कांग्रेस को सुना डाला कि उसकी 40 लोकसभा सीट जीतने की भी औकात नहीं है लेकिन फिर भी अहंकार कूट-कूट कर भरा है। राहुल गांधी अभी उत्तर प्रदेश पहुँचे नहीं हैं लेकिन उससे पहले ही वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी अभी महाराष्ट्र नहीं पहुँचे हैं लेकिन उससे पहले ही प्रकाश अंबेडकर की पार्टी इंडी गठबंधन छोड़ने की तैयारी में है। राहुल गांधी अभी दिल्ली और पंजाब नहीं पहुँचे हैं लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन से दूरी बनाने के जतन करने लगी है। सवाल उठता है कि जो नेता अपनी पार्टी और गठबंधन को जोड़े नहीं रख पा रहा है, जो नेता अपने ही नेताओं को न्याय नहीं दे पा रहा है वह दूसरों को क्या जोड़ेगा और क्या न्याय देगा? यहां एक बात और गौर करने लायक है कि एक ओर जहां राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के सांसद डीके सुरेश भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। यहां सवाल राहुल गांधी की राजनीति ही नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर भी है। जब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे से लेकर चुनावी अभियानों की रूपरेखा बनाने जैसे मुद्दों पर दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाने की जरूरत है तो राहुल गांधी दूसरे प्रदेशों में यात्रा निकाल रहे हैं। जब संसद का बजट सत्र चल रहा है और वर्तमान लोकसभा में यह मोदी सरकार को घेरने का आखिरी और बड़ा मौका है तो राहुल गांधी दिल्ली में ना होकर दूसरे प्रदेशों में यात्रा निकाल रहे हैं। यहां सवाल यह भी उठता है कि जब कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं आ रहा है तो राहुल गांधी पार्टी की जमापूंजी को भी क्यों उड़ाने में लगे हुए हैं? हम आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कांग्रेस को 452.30 करोड़ रुपये का कुल चंदा मिला लेकिन उसमें से राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गयी 'भारत जोड़ो यात्रा' पर 71.80 करोड़ रुपये खर्च हो गये। अब जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को पैसों की जरूरत है तो राहुल गांधी अपनी यात्रा का दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं जिस पर भारी भरकम खर्च आ रहा है। राहुल गांधी की पहली यात्रा पर औसतन प्रतिदिन 49 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च आया था जोकि कांग्रेस पार्टी के सालाना होने वाले खर्चों का 15 प्रतिशत बैठता है। बताया जा रहा है कि इस बार भी औसतन प्रतिदिन खर्च उतना ही आ रहा है। यानि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपय्या। इसलिए अर्थव्यवस्था पर सरकार को बड़ा-बड़ा ज्ञान देने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वह अपनी पार्टी की आर्थिक सेहत को क्यों बिगाड़ने पर तुले हैं? जहां तक इंडी गठबंधन की बात है तो सबको दिख ही रहा है कि यह टूट की कगार पर पहुँच चुका है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जब अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था तब कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी लेकिन कांग्रेस ने उनको खारिज करते हुए जीतेगा इंडिया स्लोगन दे दिया था। अब जब यह गठबंधन टूट की कगार पर है तो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर गया, इंडिया गठबंधन धराशायी। जरा सोचिये इंडिया नाम के साथ ऐसी उपमाएं सुन कर और पढ़ कर कितना दुख होता है। जो लोग कहते थे कि इंडिया की बजाय इंडी गठबंधन बोलने वाले लोग गोदी मीडिया हैं शायद उनको भी आज समझ आ गया होगा कि इंडी नाम क्यों बोला जा रहा था। इंडी इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि इस गठबंधन का यह हश्र होना पहले से नजर आ रहा था, इसलिए देश के नाम के साथ टूटने या बिखरने जैसा शब्द जोड़ना पड़े इससे बचने के लिए पहले से ही इंडी गठबंधन लिखा और बोला जा रहा था।

मोदी को क्यों नहीं हरा पाएगा इंडी एलायंस?

अजय सेतिया

अब यह सवाल नहीं है कि इंडी एलायंस मोदी को हरा सकता है या नहीं। सवाल यह है कि मोदी को विपक्षी गठबंधन क्यों नहीं हरा पाएगा ? 2014 के चुनाव के वक्त बहुत कम पत्रकार थे जो चुनावी हवा को समझ पाए थे। उस समय ज्यादातर पत्रकारों का आकलन था कि भाजपा 2004 और 2009 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने में विफल रही थी, 2014 में ज्यादा से ज्यादा वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आएगी। वे भाजपा को 200 से पार नहीं देखते थे। कुछ पत्रकार थे, जो भाजपा को नए रूप में उभरता देख रहे थे, वे भी भाजपा को 250 के आसपास ही देखते थे। लेकिन भाजपा अपने बूते पर बहुमत का आंकडा पार कर लेगी, ऐसा आकलन तो भाजपा के शुभचिंतकों को भी नहीं था।

आज करीब दस साल बाद स्थितियां पूरी तरह बदली हुई हैं। दस साल पहले जिस मानसिकता के पत्रकार भाजपा की 200 से कम सीटों का आकलन कर रहे थे, वे दस साल बाद भी 2024 में भाजपा को 200 से नीचे ही रख रहे हैं। लेकिन जो 250 के आसपास का आकलन कर रहे थे, वे 303 के पार का आकलन कर रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता से प्रभावित पत्रकारों का आकलन है कि भाजप इस बार 350 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। सहज ही सवाल उठता है कि इंडी एलायंस फेल क्यों हो गया, या फेल क्यों हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस खुद को थोड़ा सा मजबूत होता देखती है, तो घमंड के घोड़े पर सवार हो जाती है। हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन को कर्नाटक के चुनाव नतीजे तक टाला। कर्नाटक के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस के समर्थन से नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, लेकिन कांग्रेस ने दिसंबर में पांच विधानसभाओं के चुनाव नतीजों तक बात को आगे ही नहीं बढ़ने दिया।

कांग्रेस पांच राज्यों में से तीन राज्य भी जीत जाती, और ऐसा लगता कि वह लोकसभा चुनाव नतीजों में सौ से पार जा सकती है तो एक मजबूत गठबंधन बन सकता था। जो 2024 में मजबूत विपक्ष के रूप में उभर सकता था, लेकिन अब तो वह संभावना भी खत्म हो चली है। तीन राज्यों में कांग्रेस की हार के दिन से ही इंडी गठबंधन के टूटने की इबारत लिख दी गई थी। क्षेत्रीय दलों के अपने स्वार्थ होते है, वे उस राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो उनके उम्मीदवारों को जिताने की क्षमता रखता हो। पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद क्षेत्रीय दलों को यह साफ़ हो गया था कि देश की जनता कांग्रेस को कतई पसंद नहीं कर रही, इसलिए कांग्रेस उनके कंधे पर सवार हो कर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। इसलिए विपक्षी गठबंधन में नए जुड़े जेडीयू और टीएमसी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी नफे नुकसान का आकलन कर रही हैं। ममता और नीतीश कुमार अलग न भी होते, तो भी इंडी एलायंस के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। देश ज्यादा से ज्यादा इंडी एलायंस को मजबूत विपक्ष के तौर पर उभारने के बारे में सोचता।

सच यह है कि जब तक कांग्रेस वक्त के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करके खुद को मजबूत नहीं करेगी, तब तक देश की जनता भाजपा और मोदी को ही वोट देती रहेगी। नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने से एक और बड़ा अंतर आया है, जिसने राष्ट्रीय विकल्प के रूप में कांग्रेस को कमजोर और भाजपा को मजबूत किया है। भ्रष्टाचार और अल्पसंख्यकवाद के कारण 2014 में कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों को जनता ने नकारा, यह बात अब पुरानी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने नए तरह की राजनीति शुरू की है, जिसमें देश के समावेशी विकास के साथ साथ प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी उभारा जा रहा है। आज़ादी के बाद से देश की 85 प्रतिशत हिन्दू जनता जिस घुटन को महसूस कर रही थी, मोदी ने उसे उस घुटन से मुक्ति दिलाई है। काशी विश्वनाथ कोरिडोर, उज्जैन में महाकाल मन्दिर कोरिडोर के बाद अब असम में कामाख्या मन्दिर कोरिडोर और मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली कोरिडोर का विचार 80 प्रतिशत जनता को नई आज़ादी का एहसास करवा रहा है। इसी दौरान अनुच्छेद 370 का हटना और अयोध्या में राम जन्मभूमि मन्दिर का निर्माण हो जाना हिन्दू मतदाताओं में नवजागरण का संचार कर रहा है।

कांग्रेस ने राम जन्मभूमि मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा का बायकाट करके देश की 80 प्रतिशत हिन्दू जनता को संदेश दिया कि जन्मभूमि पर सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बावजूद उसकी विचारधारा और नीतियों में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मोदी की मजबूती और इंडी एलायंस की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण राष्ट्रवाद और हिंदुत्व बनाम सेक्यूलरिज्म की लड़ाई बन जाना है। हिंदुत्व बनाम सेक्यूलरिज्म का टकराव भी खुद इंडी एलायंस का बनाया हुआ है। राम जन्मभूमि पर सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद इन सभी राजनीतिक दलों के मुस्लिम नेताओं ने या तो खुलकर या दबी जुबान से सुप्रीमकोर्ट के फैसले का विरोध करके खुद को हिन्दुओं से अलग कर लिया। अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां अपने मुस्लिम नेताओं की जुबान बंद करती और सुप्रीमकोर्ट के फैसले का स्वागत करती, तो 1947 से 2019 तक राम जन्मभूमि के विरोध को जनता देर सबेर भूल भी जाती। लेकिन इन सभी दलों के हिन्दू नेता अभी भी सुप्रीमकोर्ट के फैसले पर किन्तु परन्तु लगा कर देश की 80 प्रतिशत जनता को नाराज करने की कोशिश करते रहते हैं।

शायद वे समझ नहीं पा रहे कि उनके हिन्दू विरोधी सेक्यूलरिज्म में देश की बहुसंख्य युवा पीढी की कोई आस्था नहीं है। रामजन्म भूमि आन्दोलन के बाद हिन्दू जागा है, उसने इतिहास को नए नजरिए से देखना शुरू किया है। हिन्दू ऐसा सेक्यूलरिज्म चाहता है, जिसमें उसे 500 साल की गुलामी से आज़ादी का अहसास हो। सेक्यूलर दलों की समस्या यह है कि वह ब्रिटिश काल से पहले की मुगलों की गुलामी को गुलामी ही नहीं मानते। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद स्कूलों कालेजों में वैसा ही इतिहास पढ़ाया, जिसमें मुगलकाल को गुलामी का काल नहीं माना गया था। जबकि राम जन्मभूमि आन्दोलन ने आज़ादी के बाद पैदा हुए हिन्दुओं की आँखें खोल दी। उसी का असर है कि आज हिन्दू अपने मन्दिरों को वापस हासिल करने के लिए जगह जगह आन्दोलन कर रहे हैं।

मोदी ने मन्दिरों का जीर्णोद्धार शुरू करवा कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उस अवधारणा को जमीन पर उतार दिया है, जिसका नारा 90 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने दिया था। मोदी सरकार ने आडवाणी को भारत रत्न देकर आडवाणी को नहीं देश की 80 प्रतिशत हिन्दू जनता को सम्मानित किया है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में नए आज़ाद भारत को साकार होता देख रही है। विपक्ष यह समझ नहीं पा रहा कि बदले हुए जागृत भारत में एकतरफा और फर्जी सेक्यूलरिज्म की विचारधारा भाजपा और मोदी को हराने में अक्षम है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-10)

गतांक से आगे...

पुनः जो शुद्ध वासनाओं से युक्त हैं, जो अनर्थ शून्य जीवन वाले हैं और जो ज्ञेय तत्त्व के ज्ञाता हैं, हे महान् ज्ञानी शुकदेव जी! वे ही मनुष्य पूर्ण जीवन्मुक्त कहे जाते हैं। पदार्थों की भावनात्मक दृढ़ता को ही बन्धन और वासनाओं की क्षीणता को ही मोक्ष कहा गया है।

जिसे तप आदि साधनों के अभाव में स्वभाववश ही सांसारिक भोग अच्छे नहीं लगते, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जो प्रतिपल प्राप्त होने वाले सुखों या दुःखों में आसक्त नहीं होता तथा जो न हर्षित होता है और न ही दुःखी होता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जो हर्ष, अमर्ष, भय, काम, क्रोध एवं शोक आदि विकारों से मुक्त रहता है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जो अहंकार युक्त वासना को अति सहजता से त्याग देता है तथा चित्त के अवलम्बन में जो सम्यक् रूप से त्याग भाव रखता है, वही वास्तव में जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सदैव अन्तर्मुखी दृष्टिवाला, पदार्थ की आकांक्षा से रहित और किसी भी वस्तु की अपेक्षा अथवा कामना से रहित सुषुप्ति के समान अवस्था में विचरण करता रहता है, वही मनुष्य जीवन्मुक्त कहलाता है। जो सदैव आत्मा में लीन रहता है, जिसका मन पूर्ण एवं पवित्र है, अत्यन्त श्रेष्ठ एवं शान्त स्वभाव को प्राप्त कर जो इस नश्वर संसार में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, जो किसी के प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन भाव से भ्रमण करता रहता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसका हृदय किसी भी पदार्थ में लिप्त नहीं होता तथा जो चेतन संवित् (सज्ञानयुक्त) स्वरूप वाला है, वही पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता है। जो पुरुष राग-द्वेष, सुख-दुःख, मान-अपमान, धर्म-अधर्म एवं फलाफल की इच्छा-आकांक्षा न रखता हुआ सदैव अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, वही मनुष्य जीवन्मुक्त कहलाता है।

क्रमशः ...

जब कवि प्रदीप के लिखे देशभक्ति गीत को सुनकर रो पड़े थे पं. नेहरू

देश में यूं तो कई कवि और गीतकार हुए हैं लेकिन कवि प्रदीप उन महान शख्सियों में शामिल हैं जिनके लिखे गीतों ने देशवासियों में नया जोश और जज्बा भर दिया था। उनके लिखे देशभक्ति गीत आज भी हर किसी में राष्ट्रप्रेम की भावना भर देते हैं। उनके एक गीत को सुनकर तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहलाल नेहरू की आंखें भी भर आई थीं।

भारतीय कवि और प्रसिद्ध गीतकार कवि प्रदीप की आज जयंती है। उनका जन्म 6 फरवरी 1915 को हुआ था। कवि प्रदीप का पूरा नाम रामचरण द्विवेदी था। उन्हें उनके देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों' के लिए खास तौर पर जाना जाता है। ये गीत उन्होंने चीन-भारत युद्ध के दौरान शहीद हुए देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा था।

बता दें कि उज्जैन के पास छोटे से मध्य भारतीय कस्बे बड़नगर के एक मध्यमवर्गीय औदिच्य ब्राह्मण परिवार में जन्में कवि प्रदीप ने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की थी। उन्हें बचपन से ही हिंदी कविता लिखने का शौक था। उनके लिखे देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों' से वह घर-घर मशहूर हो गए थे। दरअसल चीन से युद्ध हारने के बाद देश के नौजवानों में निराशा भर गई थी जिसके बाद कवि प्रदीप ने अपनी कलम को बंदूक बना लिया और उन्होंने ऐतिहासिक गीत 'ऐ मेरे वतन के लोगों' की रचना कर डाली।

उनके इस गीत से जुड़ा एक वाकया भी है। 26 जनवरी 1963 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में जब 'ऐ मेरे वतन के लोगों' का गायन किया था तो इस गीत को सुनकर नेहरू जी की आंखें भर आई थी। बाद में नेहरू जी ने कवि प्रदीप को इस गीत के लिए बधाई दी थी। पंडित नेहरू ही नहीं इस गीत को सुनकर लोगों में भी देशभक्ति की लहर दौड़ गई थी। युवाओं में जोश भर गया था। कहना गलत नहीं होगा आज भी ये गीत हर किसी के रोम-रोम में बसा है।

कवि प्रदीप ने कई फिल्मों के लिए देशभक्ति गीत लिखे थे। उन्हें पहचान 1940 में आई फिल्म बंधन के लिए लिखे देखभक्ति गीतों से मिली। इस फिल्म के गीतों ने हर किसी में देशभक्ति का जज्बा भर दिया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद कवि प्रदीप को तुरंत अंडरग्राउंड होना पड़ा था ताकि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें गिरफ्तार न कर सके। कवि प्रदीप की बेटी मितुल प्रदीप ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि, 1943 में आई फिल्म 'किस्मत' में उनके पिता के लिखे गीत 'दूर हटो ऐ दुनियावालों।।' की वजह से भी ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इस वजह से उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा था। कवि प्रदीप ने अपने करियर में लगभग 1700 गाने लिखे। उन्होंने फिल्मी गीतों सहित राष्ट्रवादी कविताएं भी लिखी। 1940 में आई फिल्म चलन में चल चल रे नौजवान जैसा हिट गाना भी कवि प्रदीप ने लिखा था। कवि प्रदीप लिखते तो थे ही वहीं वे गाते भी थे। उन्होंने फिल्म 'जागृति' के 'आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की गाया भी था। उन्होंने दे दी हमे आजादी गीत लिखा था जो काफी हिट हुआ था।

क्या इमरान खान जेल से कर सकते हैं बड़ा उलट-फेर?

अभिनय आकाश

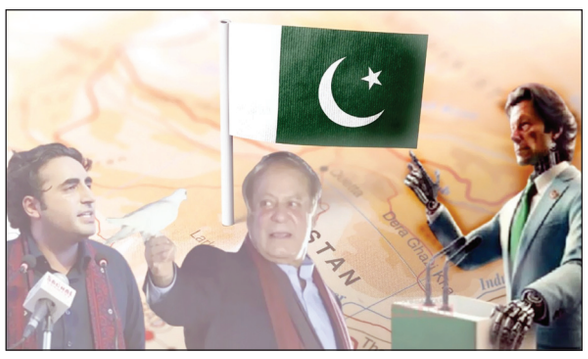

तीन दिन के बाद पाकिस्तान में चुनाव है। इमरान खान जेल के अंदर हैं। पीपीपी और पीएमएलएन के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में फौज किसे वजीर-ए-आजम के तौर पर चाहती है। पाकिस्तान में आईएसआई किसे प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होते देखना चाहता है। आपको याद होगा कि नाटकीय घटनाक्रम में इमरान खान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कमान संभाली। नवाज शरीफ की सालों बाद वतन वापसी हुई। ये चुनाव पीएमएलए नवाज शरीफ के चेहरे पर लड़ रहा है। पीएमएलए और पीपीपी के बीच मुकाबला पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा चार अलग अलग प्रांतों में है। पंजाब में इमरान खान हमेशा ही ज्यादा मजबूत रहे हैं। वहीं सिंध के बारे में कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी का यहां स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन पीएमएलए और पीपीपी के अलावा मौलाना फजुर्र रहमान की पार्टी और इमरान खान की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान के रूप में इमरान खान के पास असंभव स्थिति से मैच जीतने की क्षमता थी। वह इस आदत को दोहराने की उम्मीद करते हैं। इस बार, राजनीतिक क्षेत्र में भले ही उन्हें कई बार जेल की सजा का सामना करना पड़ा हो और पद से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो। 8 फरवरी के महत्वपूर्ण चुनाव से पहले, कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या इमरान खान, कैदी नंबर 804, असंभव काम कर सकते हैं और अपनी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को राष्ट्रीय चुनावों में जीत दिला सकते हैं? 71 वर्षीय करिश्माई व्यक्ति अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एआई से लेकर सोशल मीडिया तक इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे।

इससे पहले कि हम इस विषय पर गहराई से विचार करें कि इमरान खान सलाखों के पीछे से अपनी पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए किस तरह कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आइए इस पर करीब से नज़र डालें कि किस चीज़ ने उन्हें वहां तक ??पहुंचाया। पिछले शनिवार (3 फरवरी) को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को गैरकानूनी शादी के लिए सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस सप्ताह खान के खिलाफ यह तीसरी अदालती सजा थी। इससे पहले 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. फैसले में यह भी कहा गया कि खान को अगले 10 वर्षों के लिए सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। 30 जनवरी को खान को उनके पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ सिफर मामले में राज्य के रहस्यों को लीक करने के लिए, 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एक बात तो तय है कि इससे इमरान खान 8 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाएंगे।

वर्तमान में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इमरान खान अपने सोशल मीडिया चैनलों पर अपने विभिन्न उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए बहुत सक्रिय हैं। इसके अलावा, इमरान खान पाकिस्तान के एकमात्र नेता हैं जिनका इन सभी प्लेटफार्मों पर अकाउंट है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से इसका उपयोग कर रहे हैं कि पार्टी का संदेश सीधे लोगों के हाथों में जा रहा है। वास्तव में जब इमरान खान पिछले साल जुलाई में टिकटॉक ज्वाइन किया तो उन्हें केवल 36 घंटों में 30 लाख से अधिक समर्थक मिल गए। इमरान खान की अगुवाई वाली पीटीआई पार्टी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए समर्थन जुटाने और मतदाताओं की भावना को बढ़ाने के लिए टिकटॉक पर डिजिटल रैलियां कर रही है। प्रौद्योगिकी पत्रकार रामशा जहांगीर ने एएफपी को बताया कि उनके पास ऐप्स हैं, उनके पास ऑनलाइन भाषण हैं, उन्होंने एक टिकटॉक जलसा (सभा) किया है जो अभूतपूर्व है, कम से कम पाकिस्तान में, इसलिए उनके पास कुछ नया करने का एक तरीका है और यह हमेशा से रहा है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने 71 वर्षीय व्यक्ति का चार मिनट का संदेश तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, जो नेटब्लॉक्स के अनुसार इंटरनेट व्यवधानों के बावजूद रविवार से सोमवार रात भर सोशल मीडिया पर आयोजित एक वर्चुअल रैली का शीर्षक था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि इमरान खान ने वकीलों के माध्यम से एक शॉर्टहैंड स्क्रिप्ट भेजी थी, जिसे उनकी अलंकारिक भाषा में शामिल किया गया था। इसके बाद एआई फर्म इलेवनलैब्स के एक टूल का उपयोग करके टेक्स्ट को ऑडियो में डब किया गया, जो मौजूदा भाषण नमूनों से वॉयस क्लोन बनाने की क्षमता का दावा करता है। इमरान खान की नकल करते हुए आवाज ने कहा कि मेरे साथी पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक प्रयास के लिए सोशल मीडिया टीम की प्रशंसा करना चाहूंगा। ऑडियो को फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थकों के भाषणों की पांच घंटे की लाइव-स्ट्रीम के अंत में प्रसारित किया गया था, और इसे इमरान खान के ऐतिहासिक फुटेज और स्थिर छवियों के साथ कवर किया गया था। जिससे मतदाताओं को यह आभास हो रहा है कि पीटीआई प्रमुख उन्हें सलाखों के पीछे से संबोधित कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अनुसार इसे एक समय के क्रिकेट स्टार के पूर्व भाषणों के वास्तविक वीडियो क्लिप के साथ बुक किया गया था, लेकिन बीच-बीच में एक कैप्शन दिखाई दिया, जिसमें इसे इमरान खान की एआई आवाज उनके नोट्स के आधार पर के रूप में चिह्नित किया गया था।

इन प्रयासों के बावजूद, पीटीआई के लिए जीत दूर की कौड़ी लगती है। पार्टी के कई चर्चित सामने नहीं आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किये जा रहे हैं। इसके अलावा, पार्टी ने देश के चुनाव निगरानी संस्था द्वारा पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाना और एयरवेव्स पर इमरान खान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने जैसी सेंसरशिप का आरोप लगाया है। चुनाव पंडितों और विश्लेषकों का यह भी मानना ??है कि ऑनलाइन मजबूत उपस्थिति और सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के बावजूद उनकी पहुंच सीमित होगी। इसकी वजह पाकिस्तान का सोशल मीडिया का इस्तेमाल है. जैसा कि वाशिंगटन में विल्सन सेंटर थिंक टैंक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने बीबीसी को बताया कि पाकिस्तान की केवल 30 प्रतिशत आबादी ही सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता है। तो इससे पता चलता है कि पीटीआई सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने में जितनी अच्छी है, उनके ऑनलाइन अभियान के साथ उनकी पहुंच की अंतर्निहित सीमाएं होंगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने का भी जोखिम है, जिससे पीटीआई का वोट और अधिक विभाजित हो सकता है। इसके अलावा, एक विश्लेषक ने बताया कि यदि पीटीआई द्वारा समर्थित उम्मीदवार विजयी होते हैं, तो वे पार्टी के साथ बने रहने के लिए बाध्य नहीं हैं और परिणाम के बाद किसी अन्य समूह के साथ जुड़ सकते हैं।

आज का इतिहास

1951 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1952 एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की महारानी की गद्दी संभाली। वह उस समय महज 26 साल की थी।
1952 एलिजाबेथ द्वितीय यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तीन अन्य राष्ट्रमंडल देशों के सिंहासन के लिए अपने पिता, जॉर्ज VI की मृत्यु पर पहुंच गई।
1958 मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और कुछ प्रशंसकों और पत्रकारों को ले जाने वाला विमान पश्चिम जर्मनी के म्यूनिख में म्यूनिख-रीम हवाई अड्डे से उड़ान भरने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें आठ खिलाड़ी और 15 अन्य मारे गए।
1976 अमेरिकी सीनेट की उपसमिति के समक्ष गवाही में, लॉकहीडप्रिडेंट कार्ल कोटचियन ने स्वीकार किया कि कंपनी ने जापानी प्राइमिनिस्टर काकूए तनाका के कार्यालय को रिश्वत के रूप में 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था।
1981 बकिंघम पैलेस में प्रिंस ऑफ वेल्स ने लेडी डायना स्पेन्सर से विवाह का प्रस्ताव रखा।
1987 मैरी गौडरॉन को ऑस्ट्रेलिया की हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
1997 ओ.जे. सिम्पसन ने रॉन गोल्डमैन और निकोल सिम्पसन की हत्याओं में इसे उत्तरदायी पाया।
1998 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बिल क्लिंटन, राष्ट्रपति का कहना है कि 'वह कभी भी इस देश से नहीं चलेंगे और जिस जोर से उन्होंने मुझे रखा है, उससे दूर चले जाएंगे।
2000 तारा हेलोनन फिनलैंड के पहली महिला अध्यक्ष चुनी गयी।
2000 द्वितीय चेचन युद्ध: रूस ने चेचन्या की राजधानी ग्रोज़नी पर कब्जा कर लिया, जिससे अलगाववादी चेचन सरकार निर्वासित हो गई।
2005 टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 2,838 दिनों तक बने रहे।
2008 अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आए तूफान से भारी तबाही हुई।
2010 पाकिस्तान में तालिबान ने हुवायद में लड़कियों के स्कूल को उड़ा दिया और सौभाग्य से किसी की मौत नहीं हुई।
2011 मिस्र के लोगों ने ताहिर स्क्वायर में 13 वें दिन अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और शहीदों के दिन को आजादी की लड़ाई में मारे गए लोगों का सम्मान करार दिया।
2012 महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन के सम्राट बनने की अपनी 60 वीं वर्षगांठ और देश में सात संप्रभु होने की घोषणा की।
2013 8.0 की तीव्रता वाले भूकंप से सोलोमन द्वीप के तट पर ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ।

देश की सुरक्षा और सीमा निगरानी के लिए ड्रोन की अपरिहार्यता

धनेंद्र कुमार

आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक तनाव, संघर्ष और युद्ध में ड्रोन का अत्यधिक महत्व है। अक्सर खबरों में देखा जाता है कि रूस-यूक्रेन के युद्ध, मध्य पूर्व की तनावपूर्ण स्थिति और अनेक देशों द्वारा सीमा पर निगरानी और युद्ध के दौरान शत्रु के क्षेत्र में हमलों के लिए ड्रोन का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। ड्रोन का अर्थ मुख्य रूप से एक रिमोट कंट्रोल या कंप्यूटर द्वारा निर्देशित मानवरहित उपकरण है। इनका उपयोग रक्षा, निगरानी और आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, भू-स्थानिक मानचित्र, खनन, हवाई फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफी आदि क्षेत्रों में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

भारत ने शुरुआत में सैन्य ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल युद्ध दौरान किया था जहां इजरायल ने भारत को आईएआई हेरॉन और सर्चर ड्रोन दिये थे। तब से आज तक भारत ने इजराइल, अमेरिका आदि से कई सैन्य मानव रहित उपकरण एवं ड्रोन खरीदें हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने अपना घरेलू मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी) भी विकसित किया है। अभी हाल में ही सोमालिया के पास एमवी लीला समुद्री जहाज के हाइजैकिंग में भारतीय नौसेना ने आनन फानन में एक ऑपरेशन में एमक्यू-9बी ड्रोन को तैनात किया और 15 भारतीय चालक दल को बचाया। जून 2021 में जम्मू में भारतीय वायुसेना के एक स्टेशन पर हमले के लिए पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया था। जिसका भारत ने प्रभावी तरीके से जवाब दिया था। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में सीमा निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। भारत और चीन के बीच तनाव के

दौरान भी ड्रोन के इस्तेमाल ने आर्मी को सतर्क किया था। ड्रोन के माध्यम से स्थितिजन्य निगरानी की जा सकती है और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है।

भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के आस-पास के समुद्र क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा कार्यों के लिए भी ड्रोन का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। ड्रोन समुद्री गतिविधियों की निगरानी करने, शिपिंग लेन की सुरक्षा और तस्करी, डकैती जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करता है। 2020-21 में भारत ने कोविड महामारी के दौरान न केवल पूरे भारत में पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में शीघ्रातिशीघ्र वैक्सीन और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने में, बल्कि निकटवर्ती देशों की सहायता, जैसे नेपाल के दूर-दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इस माध्यम से कठिन इलाके और सीमित पहुंच की चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन द्वारा खेतों और फसलों पर दबाइयों के स्प्रे में भी इनका विशेष उपयोग होता है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय नौसेना को हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित यूएवी दृष्टि 10 स्टार लाइनर उपलब्ध हुआ। यह भारत की एक प्रमुख निजी कम्पनी अडानी डिफेंस एण्ड ऐरोस्पेस ने बनाया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने इसकी विशेष सराहना करते हुए यह कहा कि संघर्ष के समय समुद्री सुरक्षा के लिए ड्रोन आसमान में तीसरी आंख' साबित हो सकता है। दृष्टि 36 घण्टे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है और यह 450 किलोग्राम पेलोड वाली क्षमता का मानवरहित ड्रोन है। इस ड्रोन को स्टानाग 4671 सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, इसके चलते यह नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय सेना को 4 मेल ड्रोन की आपूर्ति के लिए अडानी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस से अनुबन्ध किया था, जिनमें इन्हें दो-दो अगले कुछ महीनों में ही उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

सैन्य ड्रोन उद्योग में निजी क्षेत्र का योगदान बहुत सामयिक है, जो भारतीय रक्षा को सामरिक लाभ और नई ऊंचाई प्रदान करेगा। कई सरकारी और निजी संस्थानों में ड्रोन से जुड़े हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने फरवरी 2021 में भारत की पहली ड्रोन फ्लाइंग साइट पर डीजीसीए प्रमाणित प्रशिक्षण शुरू किया। आत्मनिर्भर भारत नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरण के लिए 120 करोड़ रूपये के लागत की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। 2022-23 के बजट में ड्रोन शक्ति योजना की भी घोषणा की गई थी, इसके तहत ड्रोन-एस-ए-सर्विस के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ सभी राज्यों में चुनिंदा आईटीआई में कौशल विकास के लिए ड्रोन से जुड़े हुए पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। इस समय भारत में ड्रोन के निर्माण के लिए 333 स्टार्ट-अप स्थापित हो चुके हैं, और देश के नौजवानों और उधमियों द्वारा और नी तेजी से विकसित किये जा रहे हैं। पड़ोसी देशों में बढ़ती चुनौतियों और भू-रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत इस क्षेत्र में जल्द से जल्द आत्मनिर्भरता हासिल करे। इसके लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना जरूरी है। जैसे-जैसे दुनियाभर में प्रगति हो रही है भारत पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस दृष्टि से भारत में जहां आत्मनिर्भरता के लिए डीआरडीओ और पब्लिक सेक्टर में ड्रोन निर्माण और टेक्नोलॉजी में तेजी से विकास किया जा रहा है, वहीं प्राइवेट सेक्टर द्वारा इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ ही मित्र देशों से भी उच्च तकनीक और संयुक्त निर्माण के लिए करार किये जा रहे हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के साथ रक्षा समझौते में भारत ने 30 एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता किया था। इस वर्ष भारत अपने गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह में देश के सैन्य बल और सुरक्षा उपकरणों का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ। इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। उनकी दो दिवसीय यात्रा पर भारत और फ्रांस सरकार के बीच कई मुद्दों पर समझते हुए। इसमें एक रक्षा समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान साथ विकसित करने का एक महत्वाकांक्षी औद्योगिक रोडमैप जारी किया है। आज जब हमारे देश को कुछ पड़ोसी देशों और अन्य तत्वों से सुरक्षा और तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, यह अपरिहार्य है कि हमारे सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण, जिनमें उच्च-स्तरीय ड्रोन का विशेष महत्व है, उपलब्ध कराए जाएं और यह संतोष का विषय है कि हमारी सरकार और प्राइवेट क्षेत्र दोनो मिलकर इस बारे में तेजी से काम कर रहे हैं।

राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का चीन प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा

विकास मिश्रा

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का चीन प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा है लेकिन हकीकत यही है कि हर संकट के समय मालदीव का साथ भारत ने दिया है, न कि चीन ने! चीन चाहे भी तो भारत से जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता क्योंकि भारत से मालदीव की दूरी महज 820 किलोमीटर है जबकि चीन से उसकी दूरी 4 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा है। यही कारण है कि जब भी मालदीव संकट में आया तो भारत ही तारणहार बनकर वहां पहुंचा है। मालदीव को एहसान-फरामोशी के रास्ते पर ले जाने के लिए निश्चय ही चीन ने उन्हें प्रलोभन दिया होगा लेकिन यह कितना भारी पड़ने वाला है, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मोइज्जू ने अपना चुनाव 'इंडिया आउट' के नारे के साथ लड़ा था। उनका कहना है कि भारत के जो 77 सैनिक वहां रह रहे हैं, उन्हें भारत वापस बुलाए। सवाल यह है कि ये सैनिक वहां करते क्या हैं? निश्चय ही वे टोही विमानों से हिंद महासागर की निगरानी करते हैं लेकिन मोइज्जू यह क्यों भूल गए कि ये सैनिक अपने डोर्नियर विमान और हेलिकॉप्टर से मालदीव के 200 छोटे-छोटे द्वीपों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। हो सकता है कि चीन ने इससे ज्यादा सहूलियत देने की बात की हो और मोइज्जू उस प्रलोभन में आ गए हों। मामला चाहे जो भी हो लेकिन मोइज्जू जो कर रहे हैं, उससे मालदीव संकट में ही फंसने वाला है। भारत के लिए मालदीव सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और अपने सैनिकों को वहां से वापस लाकर हम चीन के लिए खुला समुद्र नहीं छोड़ सकते! हालांकि मौजूदा स्थिति में चीन वहां नहीं आ सकता लेकिन वह कोशिश तो कर ही रहा है! ऐतिहासिक तथ्य यही है कि हर संकट के समय भारत ही मदद के लिए मालदीव पहुंचा है। 1988 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के खिलाफ पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम का साथ लेकर मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी और उसके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने विद्रोह कर दिया था। माले के हुलहुले हवाई अड्डे और टेलीफोन एक्सचेंज पर कब्जा कर लिया था। गयूम की जान संकट में थी लेकिन राजीव गांधी के निर्देश पर भारतीय सेना के कमांडो ने तत्काल वहां पहुंच कर विद्रोह को असफल कर दिया। सुनामी के समय जब मालदीव के तट तबाह हो गए थे तब मदद के लिए भारत ही पहुंचा था। न केवल राहत सामग्री पहुंचाई गई बल्कि एक अस्पताल भी स्थापित किया गया था। उस राहत अभियान पर भारत ने करीब 37 करोड़ रुपए खर्च किए थे। व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत ने मालदीव को 10 करोड़ रुपए अलग से दिए। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भी मालदीव को हर तरह से मदद देने की नीति जारी रही। दिसंबर 2014 में मालदीव के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई और माले बूंद-बूंद पानी के लिए तरसने लगा तब मालदीव के आग्रह पर भारत ने 6 विमानों के माध्यम से और बाद में पानी के जहाज से भरपूर पानी पहुंचाया। इतना ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड के समय भारत ने मालदीव की हर तरह से सहायता की। मेडिकल टीम भेजी और दवाइयां पहुंचाईं। भारत में वैक्सीन लगाने की शुरुआत होने के साथ ही भारत ने तत्काल मालदीव को भी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए। न केवल पहला डोज बल्कि दूसरे डोज के लिए भी भारत ने टीके उपलब्ध कराए। कोविड के समय भारत ने मालदीव को करीब 2 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की। इसके अलावा भी भारत हर संभव सहायता करता रहा है। हम भारतीयों के संस्कार ऐसे हैं कि हम मदद करते हैं पर कभी एहसान नहीं जताते लेकिन जब कोई देश एहसान-फरामोश हो जाए तो उसे याद दिलाना बहुत जरूरी है कि यदि हमें तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें हमारी ज्यादा जरूरत है। मोइज्जू को जल्दी अक्ल आ जाए तो दोनों देशों का भला है। अन्यथा चीन तो मजे लेने के मूड में है ही!

भारत में भी मौजूद है एक मिनी फ्रांस क्या है पुडुचेरी का पेरिस कनेक्शन

अभिनय आकाश

फ्रांस द्वारा भारत में अपने पूर्व औपनिवेशिक क्षेत्रों को छोड़ने के सत्तर साल बाद पुडुचेरी में फ्रांसीसी प्रभाव के निशान मौजूद हैं। इसका प्रभाव भाषा, वास्तुकला और भोजन में देखा जाता है। पुडुचेरी के निवासी फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के एक सकारात्मक पहलू को याद करते हैं, जहां स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक और कानूनी रूप से फ्रांसीसी नागरिक माना जाता था। आज, आर्थिक और सैन्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत और फ्रांस के बीच संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। पुडुचेरी एक समय एक फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र था। उसने कुछ फ्रांसीसी तत्वों को बरकरार रखा और इसके निवासी, हालांकि भारतीय दिखते हैं, अपनी फ्रांसीसी-प्रभावित संस्कृति को संजोते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के बीच पुडुचेरी के स्थायी फ्रांसीसी कनेक्शन पर करीब से नज़र डालते हैं। पेरिस से पुडुचेरी की दूरी 8,000 किलोमीटर (5,000 मील) से अधिक है, लेकिन रंग-बिरंगी साड़ियाँ पहनने वाली कुछ महिलाएँ अभी भी फ्रेंच में बातचीत करती हैं, पुलिसकर्मी जेंडरमे की नुकीली केपी टोपी पहनते हैं और सड़क के संकेत पेरिस के प्रसिद्ध नीले और सफेद तामचीनी अक्षरों की नकल करते नजर आते हैं। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। फ्रैंकोफाइल्स का कहना है कि फ्रांस के औपनिवेशिक शासन का प्रभाव देश में अन्य जगहों पर ब्रिटिश क्रूरता से बेहतर था। बंदरगाह शहर में फ्रांसीसी अदालत में सेवा करने वाले पूर्व न्यायाधीश 96 वर्षीय डेविड एनौसामी ने औपनिवेशिक युग के नाम का उपयोग करते हुए कहा कि पांडिचेरी के भारतीयों को सांस्कृतिक और कानूनी रूप से फ्रांसीसी नागरिक माना जाता था। आज, नई दिल्ली और पेरिस बढ़ते संबंधों का जश्न मना रहे हैं, फ्रांस दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के साथ पहले से ही मूल्यवान सैन्य अनुबंध सहित आर्थिक सौदों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले जुलाई में फ्रांस के वार्षिक बैस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि थे और अब भारत में भी मैक्रों को इसी तरह सम्मान दिए जाने की उम्मीद है। भारत के दक्षिण-पूर्वी तट का क्षेत्र 1674 में फ्रांस द्वारा ले लिया गया था जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने समृद्ध मसालों और सामानों का दोहन करने के लिए एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ब्रिटेन से भारत की आजादी के सात साल बाद फ्रांस 1954 में ही चला गया और पेरिस को औपचारिक रूप से पूर्ण संप्रभुता सौंपने में 1962 तक का समय लग गया। पूर्व फ्रांसीसी व्यापारिक पोस्ट ने अपना नाम बदलकर पुडुचेरी कर लिया है, जो एक प्रशासनिक क्षेत्र है जिसमें कराईकल, माहे और यानम सहित अन्य फ्रांसीसी पूर्व-औपनिवेशिक परिक्षेत्र भी शामिल हैं। एनौसामी ने हैंडओवर के समय फ्रांसीसी राष्ट्रीयता ले ली, जिस पर उन्हें गर्व है। धाराप्रवाह फ्रेंच भाषा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसी का जन्म पेरिस में हुआ हो या किसी का जन्म पांडिचेरी में हुआ हो, दोनों के पास समान अधिकार थे। वह प्रोवेनकल-शैली बौइलाबाइस मछली सूप को अपने पसंदीदा व्यंजन के रूप में गिनता है। । फ्रेंको-भारतीय फैशन डिजाइनर वासंती मानेट ने अपने पिता की फ्रांसीसी सेना में सेवा के दौरान की एक श्वेत-श्याम तस्वीर दिखाते हुए कहा यह एक ऐसा देश है जिसे हमने अपनाया है और यह हमारा देश बन गया है। हम एक ऐसी आबादी हैं जो देखने में भारतीय लगती है लेकिन हमारी संस्कृति फ्रांसीसी है और यही बहुत खास है।

फलस्तीन का अतीत और वर्तमान

रामचंद्र गुहा

बंगलूरू में सेकेंड हैंड किताबों की दुकानों से गुजरते हुए मेरी नजर व्हेन आई लिव्ड इन मॉडर्न टाइम्स नाम के एक उपन्यास पर पड़ी। इसकी लेखिका लिंडा ग्रांट थीं, जिनका नाम मैंने पहले नहीं सुना था। लेकिन इसके शीर्षक ने मुझे आकर्षित किया, जिससे यह पता चलता था कि फलस्तीन की पृष्ठभूमि में यह उपन्यास इस्राइल के गठन से कुछ समय पहले ही लिखा गया था, जब उस क्षेत्र पर ब्रिटिशों का नियंत्रण था। यह तथ्य मेरे लिए इस उपन्यास को खरीदने के लिए काफी था। चूंकि फलस्तीन में जारी संघर्ष अभी सुर्खियों में है, लिहाजा मुझे लगा कि इससे मिलती-जुलती पृष्ठभूमि का काल्पनिक चित्रांकन राह दिखाने वाला हो सकता है। मैं निराश नहीं हुआ।

इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र बीस साल की एक यहूदी युवती इवलिन सर्ट है, जो ब्रिटेन में पली-बढ़ी, लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के तुरंत बाद वह यह देखने के लिए फलस्तीन चली गई कि वहां बनने जा रहे नए यहूदी राष्ट्र के लिए वह क्या कर सकती है। वह रास्ते में एक किबुत्ज में ठहरती है, जिसका मालिक समाजवादी विचारों वाला एक रूसी यहूदी है और जिसका आसपास के क्षेत्रों में बड़ा भारी प्रभाव है। किबुत्ज के इस कट्टरवादी नेता का उन स्थानीय फलस्तीनियों के प्रति रवैया अच्छा नहीं था, जो उसके आने के बहुत पहले से यहां रह रहे थे। वह इवलिन से कह रहे थे, अगर अंग्रेज चले गए, और हमारा उदार शासन शुरू हुआ, तो हमारे कुछ विचार उन्हें बदल देंगे। निश्चित रूप से इस विशाल रेगिस्तान में हमारे आसपास उन्हें कोई अच्छी जगह मिल जाएगी।...हम उन्हें उनकी जमीन के पैसे देंगे। हम उनके साथ

धोखा नहीं करेंगे ... हम भविष्य में विश्वास करते हैं। इसे पढ़ते हुए मुझे यहूदी विचारक मार्टिन बुबेर की याद आई, जिन्होंने वर्ष 1938 में महात्मा गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में लगभग इसी से मिलती-जुलती बातें कही थीं। हालांकि कट्टर यहूदियों के विपरीत बुबेर अरबों और यहुदियों में मेल-जोल में यकीन रखते थे, लेकिन उनका भी मानना था कि यहूदी अरबों को शिक्षित करने का काम करेंगे। खेती करने के अरबों के प्राचीन तरीकों को देखते हुए बुबेर का दावा था कि अरबों को और उनके तौर-तरीकों को बदलने के लिए यहूदी जरूरी हैं। जैसा कि उनका कहना था, यहां की मिट्टी से पूछें कि 1,300 साल तक उसके लिए अरबों ने क्या किया, और हमने मात्र पचास साल में क्या कर डाला! मार्टिन बुबेर फलस्तीन के अरबों को कमतर नस्ल के रूप में देखते थे। गांधी जी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा था, %यहां की मिट्टी हमें पहचानती है।...यहूदी किसानों ने अपने फलस्तीनी किसानों को सिखाना शुरू किया है कि खेती कैसे करते हैं। हम आगे भी इन फलस्तीनियों को सिखाने की इच्छा रखते हैं।

इवलिन किब्तुज के ग्रामीण जीवन से ऊबकर आधुनिक शहर तेल अबीव में पहुंचती है। वहां यहूदियों की आबादी में वह एक अपार्टमेंट किराये पर लेती है और एक अत्याधुनिक महिला श्रीमती लिंज से दोस्ती गांठती है, जो बर्लिन की है। शहर में एक अतिवादी युवा यहूदी से उसकी निकटता बढ़ती है, जो एक सशस्त्र अतिवादी समूह इर्गुन का सदस्य है। इर्गुन के लोग किंग डेविड होटल पर बमबारी करते हैं, जिसमें ब्रिटिशों के साथ कुछ यहूदी भी मारे जाते हैं। उपन्यास के अंत में 70 साल की इवलिन द्वारा अपने जीवन का सिंहावलोकन होता है। फलस्तीन में एक साल बिताने के बाद इवलिन ब्रिटेन चली जाती है, जहां वह एक यहूदी संगीतकार से शादी करती है। दशकों बाद पति की मृत्यु के बाद वह तेल अबीव लौटती है, जहां वह जीवन के बाकी वक्त बिताने का फैसला करती है। उसकी पुरानी पड़ोसन श्रीमती लिंज जब वह फलस्तीनियों पर इस्राइल व उसकी सेना के वर्चस्ववादी रवैये के बारे में बताती हैं, तो इवलिन को बहुत बुरा लगता है कि आखिर एक यहूदी ऐसा कैसे कर सकता है।

1990 के दशक में जब यह उपन्यास लिखा गया, तब ओस्लो समझौते की विफलता स्पष्ट हो चुकी थी और इसने लिंडा ग्रांट को 1940 के दशक में संघर्ष की उत्पत्ति का एक काल्पनिक वर्णन करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आज जबकि इस्राइल-फलस्तीन संघर्ष अपने क्रूरतम मोड़ पर पहुंच चुका है, यह उपन्यास पढ़ना काफी मार्मिक और गंभीर अनुभव था। उपन्यास यहूदियों की अद्वितीय पीड़ा, यूरोप में बड़े पैमाने पर यहूदी-विरोधी भावना, हिटलर द्वारा अंजाम दिए गए नरसंहार और इस्राइल के निर्माण के बाद भी पश्चिम एशिया के देशों में यहूदियों के उत्पीड़न की याद दिलाता है। उपन्यास खत्म करने के बाद मैंने इंग्लैंड के साहित्य में लिंडा का स्थान खोजने के लिए गूगल पर उनका नाम खोजा। मुझे पिछले नवंबर को प्रकाशित उनका एक लेख मिला, जिसमें वह इंग्लैंड के लेखकों और अभिनेताओं को लेकर शिकायत करती हैं, जो आम फलस्तीनियों का समर्थन करते हुए इस्राइली नागरिकों की हत्या पर कुछ ठोस बोलने से बचते रहे। वह कहती हैं, 'इंग्लैंड के यहूदियों के पास ऐसी कोई राजनीतिक रणनीति नहीं है, जो इस्राइल के अति कट्टर दक्षिणपंथ और हमास के अस्तित्व के बीच के विरोधाभाष को दूर कर सके।'मेरे ख्याल से अगर इस संघर्ष का कोई समाधान है, तो इसका नेतृत्व यहूदी या अरब को नहीं, बल्कि उन देशों को करना चाहिए, जो सबसे पहले इन देशों के बीच समस्या का कारण बनें। ग्रांट के उपन्यास में एक ब्रिटिश अधिकारी कहता है, 'अरबों में हमेशा से नेतृत्व और संगठन की कमी रही है और यहूदियों ने इसका पूरा फायदा उठाया है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि जमीन उन्हीं की है, जिस पर यहूदियों ने हस्तक्षेप किया है। ऐसे में, यहां पर यूरोपीय मौजूदगी फलस्तीनियों के राष्ट्रीय हित में हो सकती है।' उल्लेखनीय है कि 1917 की बालफोर घोषणा के जरिये यहूदियों के लिए फलस्तीन में एक देश बनाने का वादा करते हुए अंग्रेजों ने इस्राइल के गठन की प्रेरणा दी। यहूदियों के उत्पीड़न और फिर नरसंहार जर्मनी ने कहानी को आगे बढ़ाया। एक बार इस्राइल के बन जाने पर, खासकर 1967 के बाद फलस्तीनियों के अधिकारों के लगातार उल्लंघन को अमेरिका ने प्रोत्साहित किया। उसने इस्राइल को पैसा दिया और उसके विस्तार की योजनाओं पर आंख मूंद लीं। जाहिर है कि यहूदी या अरब से ज्यादा, वे इंग्लैंड, जर्मनी और खासकर अमेरिका हैं, जो इस्राइल-फलस्तीन संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं।

चीन पर अंकुश लगाने के लिए म्यांमार सीमा पर जरूरी है बाड़बंदी

शव शरण शुक्ला

म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध के कारण सीमा पार से शरणार्थियों एवं विद्रोहियों की आमद के चलते भारत सरकार ने म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है, ताकि बांग्लादेश सीमा की तरह मुक्त आवाजाही व्यवस्था खत्म की जाए। सितंबर, 2023 में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृहमंत्री से संदिग्ध तत्वों एवं शरणार्थियों की घुसपैठ रोकने का अनुरोध किया था। म्यांमार में उथल-पुथल और हिंसा के चलते बीते दिसंबर तक 6,000 से ज्यादा शरणार्थियों ने मणिपुर में शरण ली है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। म्यांमार के साथ मणिपुर 398 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बाड़ लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1970 में शुरू की गई मुक्त आवाजाही व्यवस्था (एफएमआर) खत्म हो जाएगी।

लेकिन मुश्किल यह है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बाड़ लगाने का विरोध किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस संबंध में अनुरोध किया है। फरवरी, 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार के 38,500 से अधिक लोगों ने मिजोरम में शरण ली है, जिससे राज्य प्रशासन पर बोझ बढ़ गया है। रखाइन प्रांत के पश्चिमी हिस्सों में जातीय अकरम सेना (एए) द्वारा सैन्य शिविरों पर कब्जा करने के बाद 500 से अधिक म्यांमार सैनिक मिजोरम में चले आए थे। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड समेत भारत के पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी खुली पहाड़ी सीमा साझा करते हैं, जिससे सुरक्षा की समस्या पैदा होती है और निवारक उपायों की जरूरत पड़ती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चीन के साथ घनिष्ठ रिश्ते को देखते हुए भारत को हिंसाग्रस्त म्यांमार में युद्धरत समूहों और सेना जनरलों के बीच शांति स्थापित करके सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्रोहियों का समर्थन करने के अलावा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के बहाने म्यांमार के नजदीक आने की चीनी रणनीति से उसे बचाने के लिए %पड़ोसी पहले% की नीति के अनुरूप एक यथार्थवादी रणनीतिक खाका विकसित करने की जरूरत है।

एक फरवरी, 2021 को जब म्यांमार में सेना ने तख्तापलट किया था, तो भारत ने सतर्क रुख अपनाया। भारत ने कूटनीतिक और अप्रत्यक्ष रूप से जुंटा का समर्थन किया था, आंग सान सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक ताकतों का खुले तौर पर समर्थन करने से परहेज किया था, जिसने अब इसे दुविधा में डाल दिया है। भारत के सामने चीन पर अंकुश लगाने की चुनौती है, जो इसलिए खतरनाक है, क्योंकि वह कुछ जातीय समूहों का समर्थन करता है।

इस जटिल परिदृश्य में %द थ्री ब्रदरहुड एलायंस% द्वारा दिसंबर, 2023 में ऑपरेशन 1027 चलाया गया था, जिसमें ता%आंग नेशनल लिबरेशन आर्मी, एए और

म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस आर्मी शामिल थी, जिसने जुंटा को हिलाकर रख दिया था। जुंटा के खिलाफ आक्रामक हमले ने इसे एक विनाशकारी झटका दिया था, जिससे चीन को इसका समर्थन करना पड़ा। %द थ्री ब्रदरहुड एलायंस% ने प्रमुख सड़कों और सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया था, जिससे नकदी संकट से जूझ रहे जुंटा के राजस्व पर असर पड़ा और उसकी आवाजाही में बाधा उत्पन्न हुई। रिपोर्टों से पता चलता है कि शान राज्य पर अचानक हुए हमलों के बाद एए ने पश्चिमी तट पर रखाइन प्रांत में अपने बेस में सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह विद्रोहियों द्वारा पूर्व में थाईलैंड की सीमा से लगे काया राज्य और भारत की सीमा से लगे सागांग क्षेत्र और चिन प्रांत तक फैला एक समन्वित प्रयास था। यह सशस्त्र समूहों और जुंटा के बीच एक साल से जारी संघर्ष विराम का उल्लंघन था।

इस साहसिक कदम से चीन के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर सेना के नियंत्रण को खतरा है, जिससे उसके हितों पर असर पड़ेगा। एलायंस देश के एक हिस्से से जुंटा को अलग करने में सफल रहा है, जिससे होकर चीन के साथ म्यामार का 40 फीसदी द्विपक्षीय सीमा व्यापार होता है; लगभग एक अरब डॉलर का व्यापार चीन में पाइप द्वारा भेजी जाने वाली प्राकृतिक गैस से होता है। इससे पहले कि इसके चलते भारत के हितों को खतरा हो, भारत को म्यांमार के प्रति अपनी पुरानी स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा। भारत का मानना है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर म्यांमार से संबंध बढ़ाने के लिए मौके का फायदा उठाए और मानवीय संकट को कम करने के लिए काम करे, जिससे जुंटा विरोधी ताकतों का समर्थन किया जा सके और संघीय लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सेना और लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक दलों से समान दूरी बनाए रखने की कोशिश की है, ताकि जुंटा चीन के पाले में न चला जाए।

जातीय संगठनों के सशस्त्र विद्रोह ने बेनकाब हुए सैन्य जनरलों को कूटनीतिक झटका दिया है, जिसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध जुंटा के लिए एक वरदान के रूप में आया था, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ उसमें व्यस्त थे। इस्राइल पर हमास के हमले ने पश्चिमी शक्तियों का म्यांमार से ध्यान हटा दिया है, लेकिन सशस्त्र समूहों के हमले से पूरा परिदृश्य बदल सकता है। म्यांमार में विपक्षी सांसदों द्वारा गठित राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी) को पश्चिम का करीबी माना जाता है, जो सशस्त्र समूहों के सफल हमले के बाद प्रोत्साहित महसूस कर रही है।

चीन ने म्यांमार से सीमा पर स्थिरता बहाल करने का आग्रह किया है, जबकि सशस्त्र समूहों के साथ जुंटा का संघर्ष तेज हो गया है। कुछ पूर्व राजनयिक चीन द्वारा अपनाई गई %दोहरी नीति% से आश्चर्यचकित हैं, जो सक्रिय रूप से उग्रवादी समूहों का समर्थन कर रहा है। म्यांमार के उत्तरपूर्वी शान प्रांत में यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी (यूडब्ल्यूएसए) को चीन से हथियार और राजनीतिक सहायता मिलती है। म्यांमार शासन ने 24 अप्रैल, 2021 को जकार्ता में अपनाए गए पांच सूत्री सर्वसम्मति समझौते को अस्वीकार कर दिया है। इसमें म्यांमार में हिंसा की रोकथाम, एक विशेष दूत का दौरा और सभी हितधारकों के बीच बातचीत शामिल थी। सैन्य जनरलों ने आसियान की शांति पहल को नजर अंदाज करने का विकल्प चुना है, जो अटकी हुई है। पश्चिम आसियान पर म्यांमार के जुंटा को अलग-थलग करने के लिए दबाव डाल रहा है।

हिचकी से हैं परेशान? तुरंत राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

हिचकी एक आम समस्या है, जो लोगों को कष्टदायक नहीं लगती है। हालांकि, कई बार बहुत से लोगों को इस तरह से हिचकी आती है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेती। इससे पेट में हलचल और सिर में दर्द होने लगता है। इस तरह आने वाली हिचकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में नीचे लिखे कुछ प्राकृतिक और घरेलू उपचार को अजमाकर इस समस्या से तुरंत राहत पा सकते हैं।

चीनी

हिचकी से राहत पाने के लिए चीनी एक लोकप्रिय घरेलू उपचार है, जिसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। इसके लिए आपको लगभग 10 सेकंड के लिए 1 चम्मच सफेद या भूरी चीनी को मुंह में रखने के बाद निगल लेना है। इसके बाद आधा गिलास पानी पी लें। दरअसल, चीनी के छोटे-छोटे दाने आपके गले में हल्की जलन पैदा करते हैं और आपका ध्यान हिचकियों से खींच लेते हैं।

नींबू

जब बात हिचकी से निपटने की आती है तो नींबू भी आपकी काफी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको बस नींबू का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखना है। इसके बाद तो इसे चबाएं और इसके रस का सेवन करते रहें। इसका खट्टा स्वाद आपकी वेगस तंत्रिका को विचलित करता है और लगातार आने वाली हिचकियों को रोकता है। नींबू का इस्तेमाल इन छोटे-बड़े कामों के लिए भी किया जा सकता है।

अचार

हिचकी का इलाज करने के लिए आप अचार या अचार के रस का सेवन कर सकते हैं। दरअसल, अचार का स्वाद हल्का तीखा होता है इसलिए यह वेगस तंत्रिका को आसानी से विचलित करके हिचकी से आपका ध्यान खींच लेता है। इसके लिए अचार के रस की कुछ बूंदें जीभ पर लगाएं या फिर अचार को तब तक चूसें जब तक आपकी हिचकी बंद न हो जाए। आपको घर पर ये 5 तरह के आम के अचार जरूर बनाना चाहिए।

सेब का सिरका

हिचकी के उपाय के रूप में आप सेब के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच सेब के सिरके को एक तिहाई कप पानी में मिलाएं और फिर इस मिश्रण को पी लें। आमतौर पर आपको इस मिश्रण के पहले दो घूंट में ही राहत मिल सकती है। यदि नहीं, तो आप थोड़ी देर बाद इसका सेवन फिर से करें। नियमित तौर पर सेब के सिरके के सेवन से स्वास्थ्य को ये लाभ मिलते हैं।

इलायची

इलायची में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी वेगस तंत्रिका, गले और फेफड़ों को शांत करने में मदद करते है। इससे हिचकी से तुरंत राहत मिलती है। इसके लिए 1 गिलास पानी उबालें और फिर उसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर 15 मिनट तक भीगने दें। इसके बाद मिश्रण को छान लें और फिर इसे थोड़ा ठंडा होने दें। हालांकि, मिश्रण को पूरा ठंडा न होने दें, इसके हल्का गुनगुना होने पर एक झटके में इसे पी लें।

बच्चों के दूध के दांत निकलने पर अपनाएं ये आसान तरीके

दर्द से मिलेगी राहत

अमूमन छोटे बच्चों को देखभाल की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहीं छोटे बच्चों के दांत निकलने पर उनकी खास देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर 6 से 9 महीने के बच्चों के दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। जब छोटे बच्चों के दूध के दांत निकल रहे होते हैं तो बच्चे के साथ ही पैरेंट्स को भी खासी परेशानी होती है। दूध के दांत निकलने के दौरान बच्चों के मसूढ़े में सूजन, दर्द और जलन की समस्या होती हैं। वहीं इस दौरान उन्हें तेज बुखार, दस्त, उल्टी और कब्ज भी होती है। बच्चे को दर्द से बचाने के लिए कुछ पैरेंट्स डॉक्टर की मदद भी लेते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के अलावा आप कुछ विशेष घरेलू उपायों की मदद से बच्चे को इस परेशानी से बचा सकते हैं। छोटे बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसे समय में उन्हें पीने के लिए तरल चीजें देनी चाहिए। इससे उन्हें ज्यादा दर्द नहीं महसूस होगा। कई पैरेंट्स बच्चे को 6 महीने बाद ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं तो उन्हें ठोस आहार खाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए पैरेंट्स अपने बच्चों के दूध में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। इससे उनके मसूड़ों को आराम मिल सकता है। साथ ही बच्चे को ठंडा दूध भी पीने को दिया जा सकता है।

शरीर की अच्छे से करें मालिश

दरअसल जब छोटे बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं तो न सिर्फ उनके मसूड़े और चेहरे में दर्द के अलावा सूजन होती है। बल्कि दर्द के कारण रोने से बच्चों के शरीर और हाथ-पैरों में भी दर्द होता है। ऐसे में आप बच्चे को आराम देने के लिए उनके शरीर की अच्छे से मालिश कर उनके दर्द को कम कर सकते हैं। हाथ-पैर की अच्छे से मालिश करने पर शरीर का बल्ड-सर्कुलेशन अच्छा रहता है। मालिश होने पर बच्चे को अच्छी नींद आती है। बच्चे के शरीर की अच्छे से मालिश किए जाने पर दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बच्चे के दांत निकलने के दौरान उनके मसूड़ों में शहद और इलायची साथ में मिलाकर लगानी चाहिए। बता दें कि इसके एंटीइंफ्लेमेटरी गुण बच्चे को होने वाली जलन और सूजन से बचा सकते हैं।

फायदों को जानकर आप भी करने लगेंगे पाइनएप्पल का सेवन!

शरीर को स्वस्थ और फिट बनाए रखने के लिए फलों का सेवन बहुत जरूरी होता हैं जिनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसा ही एक फल हैं पाइनएप्पल अर्थात अनानास जो एक स्वादिष्ट और स्वस्थ फल है। इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, फाइबर विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन के, विटामिन बी1 (थायमिन), कॉपर, फोलेट, पोटैशियम, मैगनीशियम, आयरन और मैंगनीज जैसे कई न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। दैनिक तौर पर इसका सेवन करना आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता हैं। आज इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह पाइनएप्पल का सेवन सेहत को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। आइये जानते हैं इसके बारे में...

मजबूत पाचन तंत्र

रोजाना अगर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अनानास यानी पाइनएप्पल का जूस पीते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है। यह आपका खाना पचाने में काफी ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों को खाना पचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो कई तरह की दवाइयां और घरेलु नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं। पाइनएप्पल का सेवन करने से सिर्फ पाचन ही नहीं बल्कि इसके साथ ही गैस, एसिडिटी, अपच और आपको कब्ज जैसी बीमारियों को दूर रखता है। साथ ही अनानास का जूस पीने से आपको भूख भी ज़्यादा लगती है।

स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा

पाइनएप्पल स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। पाइनएप्पल में विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा-कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद हैं। पाइनएप्पल का जूस पीने से कील, मुंहासे और एंटी एजिंग की परेशानी दूर हो जाती है। पाइनएप्पल में मौजूद गुण स्किन को ग्लोइंग और मुलायम बनाते हैं। पाइनएप्पल का जूस पीने से स्किन टैनिंग की परेशानी भी दूर हो सकती है।

कोलेस्ट्रॉल लेवल को करे कम

हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज में फैट जमा होने लगता है, जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सिट्रस फ्रूट्स मदद कर सकते हैं, जिसमें अनानास एक बेहतर ऑप्शन को सकता है। अनानास में विटामिन सी और ए अधिक मात्रा में होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। ये फल विटामिन, फाइबर और प्रोटीन तत्वों से भरपूर होता है, जिसके सेवन से ब्लड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है।

हड्डियों के लिए फायदेमंद

अनानास का जूस पीना हड्डियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। हड्डियों को मजबूती के लिए अनानास का सेवन कर सकते हैं, क्योकि इसमें मिनरल्स और विटामिन के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों कों मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।

इम्यूनिटी बढ़ाए

पाइनएप्पल सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से शरीर को दूर रखता है। इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। पाइनएप्पल का जूस पीने से ऐसी बीमारियों का खतरा दूर हो जाता है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलेन मौजूद होता है जो संक्रमण से लड़ने का काम करता है।

वजन कम करे

पाइनएप्पल का जूस पीकर वजन कम किया जा सकता है। पाइनएप्पल के जूस में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो वजन को कम करने में मदद करते हैं। ये जूस नाश्ते में शामिल कर वजन कम कर सकते हैं।

ब्लड क्लॉट बनने से रोके

हाई ब्लड प्रेशर के कारण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो जाता है, जिस वजह से ब्लड में क्लॉट बनने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। अनानास एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इनफ्लेमेटरी तत्वों से भरपूर होता है, जो ब्लड में क्लॉट बनने से रोकता है। इसे ताजा काटकर या जूस के रूप में लिया जा सकता है।

फाइबर से भरपूर

मुख्य रूप से, पाइनएप्पल फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर आपकी बॉडी के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा, पाइनएप्पल में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटैशियम, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसलिए, पाइनएप्पल खाने से हमारे शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ये आपकी बॉडी से कई तरह के टॉक्सिन्स निकाल देता है।

अस्थमा में इन चीजों को खाने से बढ़ सकती है परेशानी

आपको है ये बीमारी तो आज से बना लें दूरी

अस्थमा सांस से संबंधित बीमारी है। इसमें खांसी, सांस लेने मे परेशानी जैसे लक्षण शामिल हैं। अस्थमा के कारण ब्रोन्कियल नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न या दर्द, घरघराहट और खांसी जैसे लक्षण दिखते हैं। इन लक्षणों को रोकने के लिए डायट का सही होना जरूरी है। यहां कुछ चीजें बता रहे हैं जिन्हे खाने से अस्थमा ट्रिगर हो सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में इस तरह की चीजों से दूरी बनाना ही सही है। जानिए अस्थमा में क्या ना खाएं-

अस्थमा में ना खाएं ये चीजें

अस्थमा पेशेंट को मौजूद एलर्जी के टाइप से अलग-अलग लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में खाने की कुछ चीजों से दूरी बनाना जरूरी है। क्योंकि ये चीजें अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। इन चीजों को खाने से फेफड़ों में सूजन या सांस की नली में संक्रमण हो सकता है, जिससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

- लहसुन
- ठंडी चीजें जैसे दही या आइसक्रीम
- लैक्टोज आधारित प्रोडक्ट जैसे दूध और दूध से बनी चीजों
- मछली - जंक फूड
- प्रोसेस्ड चीजों से बचें

क्या शराब का सेवन सही?

रिपोर्ट्स की मानें तो अस्थमा मरीजों को शराब के सेवन की मनाही है। ये सूजन के अलावा ब्लडप्रेशर के लेवल और मोटापे को बढ़ा सकती है। शरीर में जमा एक्सट्रा फैट के कारण सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

क्या मीट खा सकते हैं?

रिसर्च के मुताबिक वेस्टर्न डायट में रिफाइंड अनाज, प्रोसेस्ड, लाल मीट, और डेजर्ट शामिल है, जिसमें प्रो-इंफ्लेमेटरी प्रभाव होता है और यह अस्थमा के रोगी के लिए सही नहीं है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को इस तरह के खाने से भी बचना चाहिए। अस्थमा से पीड़ित लोगों को खाने की उन चीजों से बचना चाहिए जो संरक्षक है क्योंकि उनमें केमिकल होते हैं और ये हाई सोडियम होते हैं, जो एलर्जी का कारण बनते हैं। ऐसे में ये अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं।

अस्थमा रोगी रोजाना करें ये 3 योगासन, सांस संबंधी परेशानियां होंगी दूर

दुनियाभर में हर साल मई माह के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इस साल विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को अस्थमा से बचाव और रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाएगा। दरअसल, अस्थमा एक ऐसा गंभीर रोग है, जो फेफड़ों पर अटैक करके सांस को प्रभावित करने का काम करता है। यदि समय रहते व्यक्ति को अस्थमा का सही उपचार न मिले तो स्थिति काफी गंभीर भी हो सकती है। हालांकि, अस्थमा रोगी के लिए योग काफी फायदेमंद माना जाता है। रोजाना कुछ योगाभ्यास करने से अस्थमा रोगियों को आराम मिल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास योगासन, जो अस्थमा रोगी की परेशानी दूर करने में मदद कर सकते हैं।

भस्त्रिका-

भस्त्रिका को करने से शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अच्छा होता है। जिससे सांस न आने या रुक-रुक कर सांस आने जैसी समस्या से निजात मिलती है। इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले पालथी मारकर बिलकुल सीधे बैठ जाएं। इसके बाद अपने शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना नाक से आवाज करते हुए सांस अंदर लें और फिर आवाज के साथ ही सांस बाहर छोड़ें। रोजाना सुबह 1 से 3 मिनट तक ये आसन करने से लाभ मिलता है।

धनुरासन-

धनुरासन का रोजाना अभ्यास अस्थमा रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करते समय व्यक्ति का शरीर एक धनुष की तरह मुड़ा हुआ होता है। इस योगासन को करते समय अपना ध्यान अपनी श्वास पर लगाएं। ये आसन आपके फेफड़ों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेटकर अपनी टागों को उलटी दिशा में मोड़कर हाथों से पकड़ लें। इसके बाद छाती के ऊपर के हिस्से को ऊंचा उठाकर इस अवस्था में कुछ देर तक बने रहें और फिर पहले वाली अवस्था में आ जाएं। ऐसा करते समय लगातार सांस लेते और छोड़ते रहें। साइनेस और अस्थमा से परेशान मरीजों के लिए अधोमुख श्वानासन भी अच्छी योग मुद्रा है। इस योग मुद्रा को करने से मन शांत रहने के साथ तनाव भी दूर रहता है।

अपच की समस्या से न हो परेशान, इन चीजों का करें सेवन, जल्द मिलेगी राहत

गर्मियों की तपिश और उमस के कारण लोगों को पसीने ज्यादा आते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी होते ही लोगों को कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ये समस्याएं छोटी है, लेकिन बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है।

गर्मियों के मौसम में अपनी सेहत को नजरअंदाज करना हर किसी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है।

इस दौरान सेहत के प्रति थोड़ी भी लापरवाही बरतने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इन महीनों में कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा अपच और पेट से संबंधित अन्य दिक्कतों से परेशान रहते हैं। गर्मियों की तपिश और उमस के कारण लोगों को पसीने ज्यादा आते हैं, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी होते ही लोगों को कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं।

ये समस्याएं छोटी है, लेकिन बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। हालाँकि, कुछ चीजों का सेवन कर कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए जानते हैं किन चीजों का सेवन करने से अपच को रोकने और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

पपीता- गर्मियों के मौसम में अपच और अन्य पाचन संबंधित समस्याओं से परेशान हो रहे हैं तो पपीता का सेवन करें। पपीता में पपैन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो पाचन में सुधार करता है। पपैन, एक ऐसा एंजाइम है, जो पेट में प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है। यहीं वजह है कि पपीता खाने से पाचन संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है।

सौंफ- पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सौंफ का सेवन करना फायदेमंद साबित होगा। सौंफ में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, जो पेट की मांसपेशियों को शांत रखने में सहायता करते हैं। इसके अलावा ये पेट की सूजन और गैस को कम करने में मदद करते हैं। अपच से छुटकारा पाने के लिए सौंफ का कच्चा सेवन कर सकते हैं।

पुदीना- गर्मियों के महीनों में पुदीने का काफी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुदीना एक प्राकृतिक पाचन सहायता है, जो पेट से संबंधित समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। पुदीने की चटनी बनाकर इसका सेवन करें या फिर गन्ने के जूस के साथ इसे लें, कई अन्य तरीकों से भी इसका सेवन किया जा सकता है।

दही- गर्मियों में दही का सेवन करने से कई लाभ मिलते हैं, जिनमें पेट की समस्या से छुटकारा भी शामिल है। दही, प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा स्रोत होती है, जिनका सेवन करने से पेट के बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। इसकी वजह से पाचन तंत्र में सुधार होता है और सूजन-कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

असली शिवसेना पर अभी भी सियासी जंग जारी

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को

शिवसेना के एक सदस्य (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा दायर याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें संविधान के दसवीं अनुसूची के तहत शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के विधायकों को अयोग्य ठहराने के महाराष्ट्र अध्यक्ष के इनकार को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता सुनील प्रभु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिका आज सूचीबद्ध नहीं की गई है, हालांकि इस पर आज सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने 22 जनवरी को याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की तारीख 5 फरवरी तय की थी। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए। 22 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दो सप्ताह के भीतर वापसी योग्य नोटिस जारी किया।

हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को

रांची। पीएमएलए (धनशोधन रोकथाम

अधिनियम) से संबंधित मामलों की सुनवाई वाली विशेष अदालत प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ दायर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगी। सोरेन की पैरवी कर रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को धनशोधन के मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था। महाधिवक्ता ने कहा, ''ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।'' विशेष अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के गिरफ्तार नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस समय विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है जब चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी।

सिसोदिया ने शीर्ष अदालत में जल्दी सुनवाई की अर्जी दी

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के जेल में बंद

नेता मनीष सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में 2023 में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपनी दो उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी दी। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि वह एक वर्ष से जेल में बंद हैं और उन्होंने इन उपचारात्मक याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं पहले ही याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दे चुका हूं। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल सबूत 338 करोड़ रुपये के 'अप्रत्याशित लाभ' की बात का समर्थन करते प्रतीत होते हैं।

तेजस्वी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजद

नेता तेजस्वी यादव की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने कथित केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद की एक अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की शिकायत को राज्य के बाहर, अधिमानत: किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यादव द्वारा दायर माफी के एक ताजा बयान को रिकॉर्ड पर लिया। पीठ ने कहा कि हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को यादव को अपनी कथित टिप्पणीकेवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं को वापस लेते हुए एक उचित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर कर अपनी कथित गुजराती ठग टिप्पणी वापस ले ली। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

राज्यसभा में संजय सिंह नहीं ले सके शपथ

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता संजय

सिंह सोमवार को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं लेंगे। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा के सभापति ने सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। आसन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर संजय सिंह को पिछले साल 24 जुलाई को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। जेल में बंद आप नेता को शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीतिगत हिरासत में सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी थी। अदालत का आदेश दो दिन बाद जारी किया गया था जब सिंह ने शपथ के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए और 5 से 9 फरवरी तक संसद के चल रहे बजट सत्र में भाग लेने के लिए अदालत का रुख किया था। सिंह के वकील ने अदालत में कहा था कि अंतरिम जमानत की याचिका पर जोर नहीं दिया गया है क्योंकि आप नेता को 7 फरवरी को सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना था।

संविधान संशोधन विधेयक सहित राज्यसभा में तीन विधेयक पेश

नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक सहित तीन विधेयक पेश किये जिनमें कुछ अपराधों में जेल की सजा के प्रावधान को हटाकर उनके स्थान पर अर्थदण्ड का प्रस्ताव किया गया है। दो अन्य विधेयक संविधान संशोधन विधेयक हैं जो आंध्र प्रदेश एवं ओड़िशा से संबंधित हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के 1974 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव है।

विधेयक के कारणों एवं उद्देश्य में कहा गया है कि इसमें आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने तथा यह सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है कि नागरिक, कंपनियां एवं व्यापार छोटी, तकनीकी एवं प्रक्रियागत गलतियों के कारण कारावास के भय से मुक्त होकर काम कर सकें। विधेयक में कुछ मामूली अपराधों में कारावास के स्थान पर अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया कि इस तरह से एकत्रित अर्थदंड की राशि को पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा करवाया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अर्थदंड के मामले में सुनवाई करने वाला अधिकारी केंद्र सरकार के स्तर पर संयुक्त सचिव और राज्य सरकार के स्तर पर सचिव स्तर से कम रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए।

उच्च सदन में आज जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने दो संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किए। उनके द्वारा पेश किए गए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ नयी जातियों को जोड़ने का प्रावधान है। मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जाति एवं

जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 भी पेश किया। उनके द्वारा पेश किए गए इस विधेयक में ओड़िशा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सूची में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें ओड़िशा की अनुसूचित जाति जनजातियों की सूचियों में कुछ नयी जातियों को जोड़ने का प्रावधान है।

लोकसभा में सीतारमण ने अधीर रंजन को दिया जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि गैर-भाजपा राज्यों को उनके वैध कर और जीएसटी बकाया से वंचित किया जा रहा है। सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में उन आरोपों को राजनीतिक से प्रेरित करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी समूहों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है।

निचले सदन में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश भर में आम धारणा है कि गैर-भाजपा राज्यों को उनके वैध बकाये से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका ताजा उदाहरण कांग्रेस शासित कर्नाटक है। सीतारमण ने इस पर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मेरी कोई भूमिका नहीं है, मुझे नियमों का 100 प्रतिशत पालन करना होगा, और मैंने यही किया है। उन्होंने वित्त आयोग द्वारा राज्यों को करों के हस्तांतरण का निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया।

सीतारमण ने कहा, वित्त आयोग सिफारिशें देता है जिन्हें मुझे लागू करना होता है, यह बिना किसी डर या पक्षपात या ऐसी किसी बात के किया जाता है। इसलिए यह आशंका कि कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है, एक राजनीतिक रूप से विकृत कथा है, जिसे कहते हुए मुझे खेद है, निहित स्वार्थी लोग इसे कहने में खुशी महसूस करते हैं।

उन्होंने कहा, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई भी वित्त मंत्री हस्तक्षेप कर सकता है। %मुझे यह राज्य पसंद नहीं है कि भुगतान रोकें। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष कर मामलों में राज्यों को हस्तांतरण होता है। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया 7 फरवरी को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

कर्नाटक के सीएम ने कहा, यह विरोध इस बात को लेकर है कि केंद्र द्वारा राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। यह राजनीतिक विरोध नहीं है। यह राज्य में सूखा पड़ने पर भी केंद्र सरकार के सौतेलेपन का विरोध है। इसलिए हमने 7 फरवरी को जंतर-मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।% सिद्धारमैया ने कहा,%इस साल बजट का आकार बढ़ा है, हालांकि हमें 50 फीसदी से कम दिया गया है। हमारे हस्तांतरण और अनुदान में कटौती कर दी गई है। वे उपकर और अधिभार बढ़ा रहे हैं। लोगों को हिस्सा नहीं देते हैं। इसलिए हम इसे वित्त आयोग के समक्ष मजबूती से लड़ेंगे।

विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों को परेशान कर रहा केंद्र : विपक्ष

नयी दिल्ली। बेरोजगारी तथा अमीरों एवं गरीबों के बीच बढ़ती खाई को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 'संघवाद' के सिद्धांतों को ताक पर रखकर उन राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, जहां उसकी पार्टी की सरकार नहीं है। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है।

चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर राय ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'विकसित' और 'अमृत' शब्दों का बार-बार उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग 'हलाहल' पीकर जी रहे हैं, उन्हें यह अमृत शब्द बार-बार सुनकर लगता है कि कहीं वे परलोक में तो नहीं चले गये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ष दो करोड़ नौकरी दिए जाने का वादा किया था और उसके अनुसार अभी तक बीस करोड़ नौकरी दी जा चुकी होती। उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने अभिभाषण में इस बात को क्यों नहीं बताया कि अभी तक कितनी नौकरियां दी गयी? उन्होंने कहा, ''क्या यह (नौकरी देने का वादा) भी एक जुमला था?''

राय ने कहा कि संसद से 146 सांसदों को निलंबित कर कानून पारित किए गए। उन्होंने इस घटना की जर्मनी में हिटलर के शासन से तुलना करते हुए कहा कि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार के इस 'रिपोर्ट कार्ड (राष्ट्रपति अभिभाषण)' में बड़े बड़े दावे किए गए हैं किंतु जमीन पर कुछ नहीं है। उन्होंने 15 जनवरी को जारी ऑक्सफेम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में एक प्रतिशत संपन्न लोगों के पास देश की 40 प्रतिशत संपदा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निगमित करों में कटौती कर रही है वहीं केंद्रीयकृत कर जीएसटी में बढ़ोत्तरी कर परिवारों पर परोक्ष करों का बोझ बढ़ा रही है।

तृणमूल सदस्य ने कहा कि भारत में महिलाओं की मेहनत पर जो आय होती है वह पुरूषों की आय की तुलना में एक रूपये पर 63 पैसे है। उन्होंने कहा कि भारत में अरबपतियों की संख्या में बढ़ी है। राय ने यूएनडीपी की 15 जनवरी को जारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश की 10 प्रतिशत आबादी को देश की 57 प्रतिशत आय प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश की 10 प्रतिशत आबादी देश की 65 प्रतिशत संपदा को नियंत्रित करती है, जिससे देश में संपदा वितरण में भारी असमानता का पता लगता है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में प्रवासी मजदूरों के गरीबी रेखा से नीचे चले जाने की आशंका जताई गई है।

उन्होंने कहा कि भारत में 35 प्रतिशत कार्यबल का वास्तविक वेतन 2014 से बिलकुल नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख या चर्चा नहीं की गयी है। राय ने कहा कि सरकार पहले 'सहयोगात्मक संघवाद' का खूब उल्लेख करती थी किंतु अब वह इसकी कोई चर्चा नहीं करती क्योंकि अब यह 'असहयोगात्मक संघवाद' हो गया है। तृणमूल सदस्य ने कहा कि जो राज्य विपक्षी दलों की सरकारों द्वारा शासित हैं, उनके नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के जरिये परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों को विभिन्न तरह के हथकंडे अपना कर सत्ता से हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''यह प्रतिदिन हो रहा है और यहां तक कि एक दलित मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा गया।'' उन्होंने प्रश्न किया कि एक देश, एक चुनाव की बात कहां से आयी, क्या यह संविधान में है या इसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग ने की है? उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि एक पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर इस काम को युद्धस्तर पर किया जा रहा है। राय ने कहा कि यह दमनकारी सुझाव है और उनकी नेता ममता बनर्जी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने इससे असहमति जतायी है। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारिया आयोग की सिफारिशें क्यों लागू नहीं कर रही है? उन्होंने कहा कि केंद्र उनके राज्य पश्चिम बंगाल में 'राजकोषीय आतंकवाद' मचा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में 100 से अधिक बार केंद्रीय एजेंसियों को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पूरे देश में एकमात्र पश्चिम बंगाल राज्य को ही निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के एक लाख 16 हजार करोड़ रूपये रोक दिये गये हैं। उन्होंने दावा किया कि यह 'आर्थिक नाकेबंदी है और वे गरीब लोगों को मारना चाहते हैं। यह राजकोषीय आतंकवाद है।'

खेल
प्रमुख समाचार

भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 106 रनों से चटाई धूल

विशाखापट्टनम। भारत और इंग्लैंड के बीच

विशाखापट्टनम में गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 106 रनों से हरा दिया है। इस मैच में भारत से इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 292 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 106 रनों से मैच जीत लिया। भारत के लिए इस जीत के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे। उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 9 विकेट हासिल किए हैं। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल इस मैच में दोहरा शतक लगाया तो वहीं शुभमन गिल ने शतक लगाया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है।

पहला सेशन - इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली (29) और रिहान अहमद (9) दिन की शुरुआत करने के लिए पहले सेशन में आए। इन दोनों ने टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंचा कि तभी रिहान अहमद को अक्षर पटेल ने 23 रन के स्कोर पर पवेलियन की रहा दिखा दी। इसके बाद क्रीज पर आए ओली पोप 23 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने और फिर 16 रनों के निजी स्कोर पर जो रूट को भी अश्विन ने चलता कर दिया। इंग्लैंड के जैक क्रॉली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 132 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के के साथ 73 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी का अंत कुलदीप यादव ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर किया। पहला सेशन खत्म होने से पहले जसप्रीत बुमराह ने जॉनी बेयरस्टो को 26 रन बनाकर आउट हो गए।

दूसरा सेशन - इंग्लैंड के लिए दूसरे सेशन की शुरुआत बेन स्टोक्स और बेन फोक्स ने की। इस सेशन की पहली विकेट भारत के लिए रन आउट के रूप में आई। बुमहार ने टॉम हार्टले को 36 रनों स्कोर पर बोल्ड कर इंग्लैंड की दूसरी पारी को 69.2 ओवर में 292 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 106 रनों से मैच जीत लिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में गिरावट सेंसेक्स 390 अंक लुढ़का

मुंबई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बीएसई पर सेंसेक्स 390 अंकों के गिरावट के साथ 71,725 पर क्लोज हुआ। एनएसई पर निफ्टी 0.39 फीसदी के गिरावट के साथ 21,767 पर बंद हुआ। आज के कारोबार के दौरान कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, सिप्ला टॉप गेनर के लिस्ट में शामिल रहे। यूपिएल, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व ने गिरावट के साथ कारोबार किया है। यूपियल 11.18 फीसदी गिरकर 474.00 रुपये पर बंद हुआ। सेक्टर के मोर्चे पर, ऑटो, फार्मा, मेटल, तेल और गैस, बिजली और रियल्टी 0 ।5-1 फीसदी ऊपर रहे। भारतीय रुपया शुक्रवार के 82.92 के मुकाबले सोमवार को 14 पैसे गिरकर 83 ।06 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सुबह के कारोबार में बेंचमार्क सूचकांकों की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन दिन के दौरान उनमें सुधार हुआ और हरे निशान में कारोबार हुआ।

योगी सरकार ने पेश किया 7.36 लाख करोड़ का बजट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2024-25 का बजट आज पेश हुआ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा, लखनऊ में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को लागू किया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामूहिकता में उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के परिणामस्वरूप ग्लोबल माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2023 में इन्वेस्टर समिट आयोजित होगी, जिससे प्रदेश में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का तीसरी तिमाही में मुनाफा 91.3% बढ़ा

नईदिल्ली। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में शुद्ध लाभ 91.3 प्रतिशत बढ़कर 75.03 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में मुनाफा 39.22 करोड़ रुपये था। टीआरएसएल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि तीसरी तिमाही में शुद्ध राजस्व बढ़कर 954.68 करोड़ रुपये हो गया। यह 2022 में समान अवधि में 766.4 करोड़ रुपये था। टार्सल के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक उमेश चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मजबूत प्रदर्शन निरंतर परिचालन गति को दर्शाता है। टीआरएसएल रेल गाड़ी, घटकों, यात्री डिब्बों और मेट्रो के डिब्बों सहित यात्री तथा माल ढुलाई रेल प्रणालियों दोनों में अपनी उपस्थिति के साथ गतिशीलता समाधान प्रदान करती है।

सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 6 महीने के उच्चतम स्तर पर

नईदिल्ली। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और सकारात्मक मांग के दम पर जनवरी में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जनवरी में 61.8 पुहंच गया। यह दिसंबर में 59 पर था। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र की करीब 400 कंपनियों को भेजे गए प्रश्नावली के जवाबों पर आधारित है। एचएसबीसी के अर्थशास्त्री इनेस लैम ने कहा, भारत की सेवा पीएमआई जनवरी में छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। नए व्यवसाय का विस्तार तेज गति से हुआ।

युवा भारत को लुभा रहे वित्त मंत्री के ये वादे

सुधा श्रीमाली

लंबे समय से कम आय वर्ग के लोगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत की समस्या है। जबकि टॉप ऑफ द पिरामिड की ग्रोथ तेजी से हो रही है। अब कोशिश है कि खपत बढ़े।

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब गुरुवार को 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश कर रही थीं, तब यह मिनट-दर-मिनट साफ होता जा रहा था कि सरकार बजट को देखने की भारतीय मानसिकता को बदलने के मूड में है। सालों से बजट में लोकलुभावन घोषणाओं के आदी भारतीयों को वित्त मंत्री एक ऐसे लोक में लेकर गईं, जहां हर किसी के लिए मौके, रोजगार, साफ पानी-हवा, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, बेहतर इंफ्रा से लेकर ग्रोथ की ऐसी इन्क्लूसिव अप्रोच होगी, जिससे भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पा लेगा।

यह अचीव करने के लिए उन्होंने जीडीपी की नई परिभाषा गढ़ते हुए गवर्नेंस, डिवेलपमेंट और परफॉरमेंस के बूते भारत की नई चार जातियां- 'महिलाएं, किसान, युवा और गरीब' सेंट्रिक पॉलिसी का खाका खींचा। एक अर्थशास्त्री ने बताया कि देश की यंग एस्पिरेशनल आबादी को विकसित भारत की नींव मजबूत करने की गारंटी देने और बिग पिक्चर दिखाने वाले ऐसे स्टेटमेंट बहुत आकर्षक लग रहे हैं। स्थिति यह है कि मौजूदा समय में शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रा की जो हालत है, उसे वह छोटे-छोटे इश्यू समझ कर उम्मीद से बड़ी तस्वीर की ओर देख रहा है। शायद उसे सरकार के इरादों पर भरोसा है। सरकार ने मौटे तौर पर कोशिश की है कि खपत बढ़े। लंबे समय से समाज में कम आय वर्ग के लोगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत की समस्या है, जबकि टॉप ऑफ द पिरामिड की ग्रोथ तेजी से हो रही है। ऐसे में सरकार ने इन्क्लूसिव ग्रोथ के लिए एग्री, रूरल, विमिन, हाउसिंग पर खर्च को बढ़ाया है। सरकार ने रोड, वॉटर, इंफ्रा, रेलवे, एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा, रिसर्च, इनोवेशन, सोलर, डिफेंस आदि में भविष्य के भारत के लिए निवेश किया है। इसे करते हुए वित्तीय समझदारी का भी ध्यान रखा है।

राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए घाटे के लक्ष्य को संशोधित कर इसे जीडीपी का 5.8 फीसदी कर दिया है। 2025 में इसे जीडीपी के 5.1 फीसदी पर रखने का एस्टिमेट यह दिखाता है कि नए भारत के लिए मौजूदा सरकार कर्ज ही नहीं, निवेश की गुंजाइश भी छोड़ना चाहती है। भारत की नेट बोरोविंग 11,75,000 करोड़ रुपये और निवेश 11,11,000 करोड़ रुपये है। बहुत कम देश ऐसे हैं, जो उतना निवेश कर रहे हैं, जितना बॉरो कर रहे हैं। जहां तक ग्रोथ की बात है तो रिवाइज्ड एस्टिमेट से 17 फीसदी ज्यादा है। अंतरिम बजट में भारत को बड़े लक्ष्य के लिए काम करने की ओर रास्ता बनाने की कोशिश की है। इससे ग्लोबल और घरेलू दोनों तरह के निवेशकों को फायदा होगा। आज भारतीय बाजार जिस प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, वह दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत आगे है। चीन से तीन गुना और रूस से 8 गुना प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे भारत पर सभी की नजर है। एवरेज रियल इनकम में 50 फीसदी बढ़ोतरी होने की बात जब वित्त मंत्री बजट में कर रही थीं, तब मौजूदा हालात से मिस-मैच हो रही आम आदमी की माली हालत उम्मीद के दीए जलाए बजट भाषण सुन रही थी। उसे लग रहा था कि उसमें 'उसका टाइम भी आएगा।' वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी। हालांकि 25,000 रुपये तक की छोटी राशि के टैक्स मांग को लेकर विवाद से आम लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया। एक घंटे से भी कम के अपने बजट भाषण में उन्होंने पिछले 10 साल में सरकार की उन उपलब्धियों को रखा, जिससे देश 'नाजुक अर्थव्यवस्था' की श्रेणी से बाहर निकल कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं होने पर और तुरंत कोई लाभ नहीं मिलने पर भी मिडिल क्लास शायद यह सोच रहा है कि तीसरे कार्यकाल में वापस आने की इच्छा रखने वाली सरकार की यह बिग पिक्चर है।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मोदी की गारंटी
विष्णु का सुशासन

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

हमने बनाया है
हम ही संवारेंगे

महतारी वंदन योजना

पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष
₹ 12,000

देखिए आवेदन फार्म कैसे भरे ?

- महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना क्रियान्वित है
- यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जा रही है
- योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा

योजनांनर्गत पात्रता

- विवाहित महिला जो छतीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो
- आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो
- स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज। (निवास प्रमाण-पत्र/ राशन कार्ड/ मतदाता पहचान-पत्र/ आधार कार्ड)
- स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड
- स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)
- महिला के विवाहित होने की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज-विवाह प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता परिचय पत्र/ निवास प्रमाण पत्र/ ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- परित्यक्ता/ तलाकशुदा होने की स्थिति में समाज द्वारा / वार्ड/ ग्राम पंचायत/ न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र/ कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची/ स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस । (कोई एक)
- पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति
- स्व-घोषणा शपथ पत्र (आवेदन के साथ संलग्न)
- यदि महिला हितग्रही के पास मोबाईल नंबर न हो तो राशन कार्ड जमा किया जावे

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता

- पात्र महिला को रुपये 1000/- प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा
- सामाजिक सहायता कार्यक्रम/विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा

आवेदन करने का माध्यम

योजना के ऑनलाईन पोर्टल
(https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in)
तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे-

- आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से
- ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से
- बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से
- आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे
- नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से

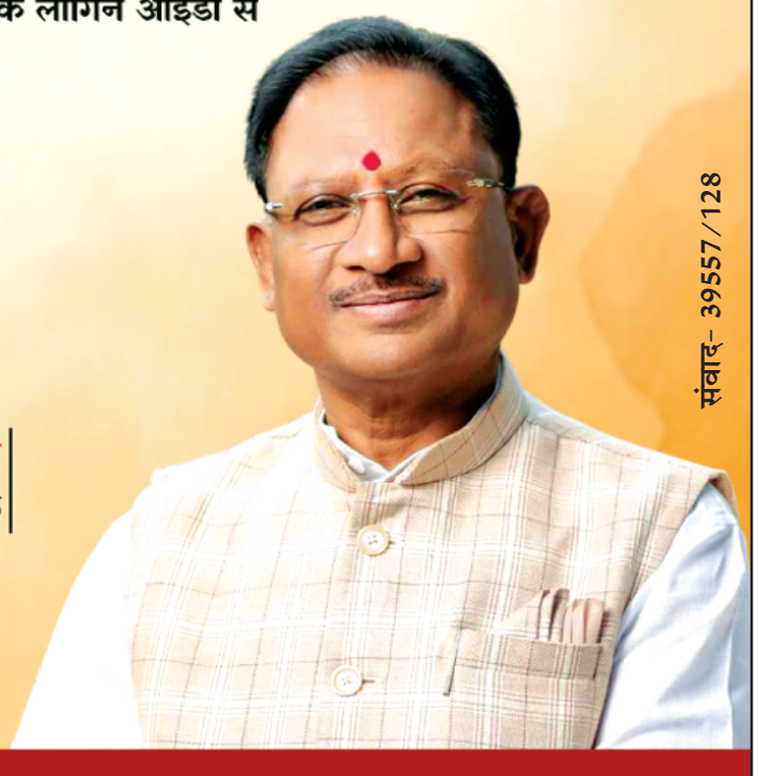

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संवाद- 39557/128

सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.